कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत कृषि अखबार

Postal R.No.MP/BPL/525/2025-27 RNI No. Raj HIN/2000/3239, डाक प्रेषण का दिन- मंगलवार, बुधवार

कृषक जगत

राष्ट्रीय कृषि अखबार

भोपाल-जयपुर-रायपुर ISSN -0970-8650

संस्थापित 1946 जयपुर, प्रकाशन - सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 वर्ष-26 अंक-3 मूल्य-12/- कुल पृष्ठ-12 www.krishakjagat.org पृष्ठ-1

कृषक जगत न्यूज़ वेबसाइट पर जाने के लिए QR कोड स्कैन करें

भाकृअनुप ICAR चौधरी चरणसिंह अवार्ड से पुरस्कृत

धनतेरस एवं दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

कृषक जगत के सुधी पाठकों, विज्ञापनदाताओं, प्रतिनिधियों एवं शुभचिंतकों को धनतेरस एवं दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।

- कृषक जगत परिवार

श्री मोदी ने किया देश की कृषि व्यवस्था में नए युग का आरंभ

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी मजबूत

किसान को अच्छा बीज, तकनीक और सलाह मिलने से कृषि में बढ़ेगी उत्पादकता : श्री शर्मा

जयपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित विशेष कृषि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरूआत की। उन्होंने देश को 24 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना एवं 11 हजार 440 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़े तथा प्रधानमंत्री के संबोधन का श्रवण किया।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धन-धान्य कृषि योजना, दलहन मिशन और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ कर देश की कृषि व्यवस्था में एक नए युग का आरंभ किया है। ये योजनाएं उत्पादन बढ़ाने के साथ ही खेती को अधिक आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने का काम करेंगी। प्रधानमंत्री की इस दूरदर्शी पहल से किसान भाई-बहन अब केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक तरीकों और बाजार से बेहतर जुड़ाव के माध्यम से समृद्धि और प्रगति का नया अध्याय रचेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का स्पष्ट मानना है कि यदि देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है, तो हमें अपने अन्नदाताओं को सशक्त बनाना होगा।

प्रदेश में 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित- श्री शर्मा ने कहा कि इस योजना का पहला लक्ष्य सिंचाई का विस्तार करना है। यह योजना प्रधानमंत्री के 'हर खेत को पानी' के सपने को साकार करने की दिशा में काम करेगी। छोटे किसानों को सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर की सुविधा मिलेगी तथा परंपरागत जलाशयों का पुनर्जीवन एवं सिंचित क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में अब तक लगभग 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में संपूर्ण सिंचित क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर संयंत्र स्थापित करना हमारा लक्ष्य है।

प्रदेश में 14 लाख सॉयल हेल्थ कार्ड जारी- श्री शर्मा ने कहा कि किसान को सही बीज, सही तकनीक और सही सलाह मिलने से ही कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी। इस योजना के माध्यम से हर जिले में मिट्टी की जांच कर सॉयल हेल्थ कार्ड बनाकर किसानों को वैज्ञानिक सलाह दी जाएगी। प्रधानमंत्री की पहल से पंचायत और ब्लॉक स्तर पर गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, साइलो और पैकिंग यूनिट बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 14 लाख सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने 97 हजार से अधिक किसानों को कृषि यंत्रों पर 546 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के माध्यम से अपनी फसल को स्थानीय स्तर पर प्रसंस्कृत कर सीधे बाजार तक पहुंचाने की सुविधा मिल रही है।

पॉलिसी धारक किसानों को 5 हजार 965 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान- मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि अवसंरचना निधि के माध्यम से दीर्घकालिक सस्ते ऋण की सुविधा दी जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान का कवच बन रही है। उन्होंने कहा कि बीते दो वर्षों में राज्य में साढ़े सात करोड़ से अधिक फसल बीमा पॉलिसी जारी की गई हैं। जिनके अंतर्गत 3 हजार 452 करोड़ रुपये का राज्यांश प्रीमियम जमा किया गया है। 1 करोड़ 76 लाख पॉलिसी धारक किसानों को 5 हजार 965 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान किया गया है। वर्ष 2025 में अब तक 2 करोड़ 16 लाख पॉलिसी जारी की जा चुकी हैं।

गौशालाओं अनुदान में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी-श्री शर्मा ने कहा कि पशुपालकों को मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों एवं कॉल सेंटर के माध्यम से घर बैठे नि:शुल्क पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बस्सी स्थित फ्रोजन सीमेन बैंक में अत्याधुनिक सीमेन उत्पादन इकाई स्थापित की गई है। मंगला पशु बीमा योजना के तहत 400 करोड़ का व्यय कर गाय, भैंस, भेड़-बकरी एवं ऊंट सहित 42 लाख पशुओं का निशुल्क बीमा किया जा रहा है। उन्होंने कहा ऊंटपालन के संरक्षण एवं नवजात टोडियों के पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया गया है। प्रदेश में गौ सेवा को बढ़ावा दिए जाने के लिए पात्र गौशालाओं में दिए जाने वाले अनुदान में 25 प्रतिशत की बढ़ात्तरी की गई है।

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में प्रदेश के आठ जिले शामिल

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत देश के ऐसे 100 कृषि जिलों को चुना गया है। कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता एवं औसत से कम ऋण उपलब्धता इन जिलों के चयन का मुख्य आधार है। देश से 100 जिलों में से राज्य के आठ जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर और चूरू को इस योजना में शामिल किया गया हैं।

प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में उठाए ठोस कदम

श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। मजबूत डिजिटल व्यवस्था से यह धनराशि बिना किसी बिचौलिए के समय पर सही लोगों तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

रामजल सेतु लिंक परियोजना से किसानों को मिलेगा भरपूर पानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के खेतों में वर्षा जल का संचयन सुनिश्चित करने के लिए अब तक 35 हजार 368 फार्म पौंड बनाए जा चुके हैं, जिन पर करीब 307 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में 7 हजार 903 डिग्गियां और 98 हजार 753 पाइपलाइन इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिन पर 400 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय हुआ है। उन्होंने कहा कि रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत पार्वती, काली सिंध, इस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिनसे किसानों को खेती के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा।

पराली प्रबंधन पर किसानों को जागरुक करना बेहद जरूरी : श्री चौहान

नई दिल्ली (कृषक जगत)। पराली प्रबंधन को लेकर नई दिल्ली, कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की संयुक्त रूप से बैठक हुई। बैठक में पंजाब के कृषि मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, हरियाणा के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री श्री मजिंदर सिंह सिरसा वर्चुअली शामिल रहे। बैठक में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने और धान पराली के बेहतर उपयोग सहित किसानों के बीच जागरुकता, वित्तीय सहायता, प्रभावी निगरानी, फसल प्रबंधन व विविधिकरण को लेकर व्यापक चर्चा हुई।

बैठक में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्रियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह को अपने-अपने राज्यों में पराली प्रबंधन की स्थिति से अवगत करवाया साथ ही बताया कि पूरी सक्रिता और सतर्कता के साथ पराली प्रबंधन की योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों, कर्मचारियों सहित पूरा विभाग गंभीरतापूर्वक कार्य में जुटा है।

बैठक में हरियाणा के कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में वित्तीय सहायता के माध्यम से किसानों को पराली ना जलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसका व्यापक असर हुआ है।

राज्यों के प्रयासों की सराहना करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि राज्यों में पराली प्रबंधन को लेकर अच्छा काम हो रहा है, लेकिन निरंतर प्रयास जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच जनजागरुकता अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए पंचायत और ग्रामीण स्तर पर जनप्रतिनिधियों व नोडल अधिकारियों की भी भागीदारी यदि सुनिश्चित की जाए, तो और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने बैठक में फसल प्रबंधन, सीधी बुवाई, विविधिकरण, राज्यों द्वारा कार्य योजना धनराशि का उचित उपयोग, प्रभावी निगरानी साथ ही साथ लक्ष्यबद्ध रूप से व्यावाहारिक योजनाओं के निर्माण को लेकर भी चर्चा की। बैठक में कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट सहित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में होगा

मतगणना 14 नवंबर को होगी

नई दिल्ली (कृषक जगत)। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर वोटिंग दो चरणों में होगी - पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को। सभी सीटों की मतगणना एक साथ 14 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार में 7.4 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 14 लाख नए वोटर शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में पुलिस अवलोकक तैनात किए जाएंगे। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए चुनाव समय पर पूरे होंगे। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटें शामिल हैं।

ई-नाम प्लेटफॉर्म का विस्तार, 9 नई वस्तुएं जुड़ीं

नई दिल्ली (कृषक जगत)। कृषि मंत्रालय ने 9 अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करके राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के दायरे का विस्तार करके इसे और मजबूत किया है, जिससे इस मंच पर व्यापार योग्य कृषि वस्तुओं की कुल संख्या 247 हो गई है।

यह महत्वपूर्ण कदम किसानों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों की निरंतर मांग को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि व्यापक कमोडिटी कवरेज और बाजार एकीकरण को और मजबूत किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य किसानों और व्यापारियों को एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में सक्षम बनाकर उनके लिए अवसरों को बढ़ाना है, जो पूरे भारत के बाजारों को जोड़ता है। जोड़ी गई 9 नई वस्तुएं इस प्रकार हैं-

- ग्रीन टी
- चाय
- अश्वगंधा की सूखी जड़ें
- सरसों का तेल
- लैवेंडर तेल
- मेंथा ऑयल
- वर्जिन जैतून का तेल
- लैवेंडर के सूखे फूल
- ब्रोकन राइस।

सोयाबीन और मक्का के दाम गिरे, किसानों को एमएसपी से कम कीमतें

नई दिल्ली (कृषक जगत)। खरीफ 2025 में प्रमुख फसलों सोयाबीन और मक्का की कीमतें कमजोर रहीं। बुवाई में कमी और एमएसपी बढ़ने के बावजूद किसानों को दोनों ही फसलों के लिए समर्थन मूल्य से कम दाम मिले।

सोयाबीन की स्थिति

कृषि मंत्रालय के अनुसार, खरीफ 2025 में

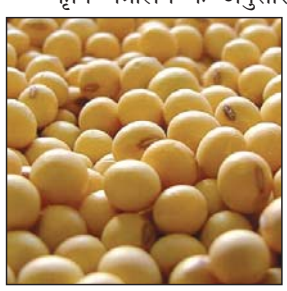

सोयाबीन का रकबा घटकर 120.32 लाख हेक्टेयर रह गया (पिछले साल 126.04 लाख हेक्टेयर)। सरकार ने एमएसपी रु. 5,328 प्रति क्विंटल तय किया है, परंतु सितंबर में देशभर की मंडियों में औसत भाव केवल रु. 4,617 प्रति क्विंटल रहे - यानी करीब 11.6 प्रतिशत गिरावट।

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में भाव 7-15 प्रतिशत तक गिरे, जबकि तमिलनाडु में रिपोर्टिंग त्रुटि जैसी असामान्य उछाल (रु. 8,562/क्विंटल) दर्ज हुई।

कमज़ोर अंतरराष्ट्रीय मांग, सोयाबीन तेल व खली के दामों में गिरावट और खराब गुणवत्ता वाली फसल ने बाजार को दबाव में रखा। किसानों को एमएसपी और वास्तविक दाम के बीच करीब रु. 1200 प्रति क्विंटल का घाटा झेलना पड़ा।

मक्का बाजार पर दबाव

सितंबर 2025 में मक्का का औसत भाव रु. 2,115 प्रति क्विंटल रहा, जो अगस्त से 9 प्रतिशत और पिछले साल से 10 प्रतिशत कम है।

खरीफ 2025 में मक्के की बोआई 18 प्रतिशत बढ़कर 94.62 लाख हेक्टेयर तक पहुंची, जिससे भारी आवक और बढ़ी आपूर्ति ने दाम नीचे खींचे।

मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भाव 18-21 प्रतिशत तक गिरे। हालांकि इथेनॉल उत्पादन की मांग बढ़ी है, परंतु DDGS जैसे सह-उत्पाद ने पशु आहार में मक्के की पारंपरिक मांग को कम किया है।

आगे की दिशा

विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले महीनों में कीमतें इस पर निर्भर करेंगी कि-

● सरकार एमएसपी पर कितनी खरीद करती है। ● इथेनॉल संयंत्र मक्का की खरीद कितनी बढ़ाते हैं, और ● अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल व अनाज की कीमतें कैसी रहती हैं।

किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसल बेचने का सही समय चुनें, भंडारण और अनुबंध खेती जैसे विकल्प अपनाकर नुकसान कम करें।

राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान का 14वाँ स्थापना दिवस

रायपुर। आईसीएआर-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान (NIBSM), रायपुर का 14वाँ स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर डॉ. मंगला राय, पूर्व सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक, आईसीएआर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डॉ. राय ने अपने महानिदेशक, आईसीएआर के कार्यकाल के दौरान इस संस्थान की परिकल्पना एवं स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

कार्यक्रम में डॉ. टी. पी. राजेन्द्रन, पूर्व सहायक महानिदेशक (पादप संरक्षण), डॉ. पियूष पाण्डेय, कुलपति, एमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ तथा डॉ. जे. कुमार, पूर्व संयुक्त निदेशक, आईसीएआर-एनआईबीएसएम विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए।

कार्यक्रम में डॉ. मंगला राय ने वन हेल्थ की अवधारणा को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा जैविक और अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन के बीच समन्वय की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी को किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु नवाचारी एवं टिकाऊ उपकरण विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। डॉ. पी. के. राय, निदेशक, आईसीएआर-एनआईबीएसएम ने संस्थान की उपलब्धियों एवं गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण किया तथा कृषि विज्ञान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन विकसित करने हेतु उच्च शिक्षा एवं क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया।

इस अवसर पर दो प्रगतिशील किसानों को सतत कृषि पद्धतियों में उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया गया। साथ ही, विभिन्न श्रेणियों में संस्थान के श्रेष्ठ कर्मचारियों को भी उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कृत किया गया।

कार्यक्रम के दौरान एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर एक संकलन, तकनीकी पुस्तिकाएँ एवं नीति पत्र भी अतिथियों द्वारा जारी किए गए।

अतिथियों का स्वागत एवं उद्बोधन तथा कार्यक्रम का समन्वयन डॉ. अनिल दीक्षित, संयुक्त निदेशक, आईसीएआर-एनआईबीएसएम द्वारा किया गया।

झुंझुनू के मंड्रेला में जल संचय-जन भागीदारी-जन आंदोलन कार्यक्रम

हर गांव, हर खेत में वर्षा जल के संचयन का लें संकल्प : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान देशभर में बनेगा जल संचयन की मिसाल : श्री पाटिल

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जल संचय-जन भागीदारी के आह्वान पर दूसरे राज्यों में बसें प्रवासी राजस्थानी अपनी मातृभूमि को जल आत्मनिर्भर बनाने के आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी भी हर गांव, हर खेत में वर्षा जल की एक-एक बूंद को सहेजने का संकल्प लें और आने वाली पीढ़ियों को एक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य प्रदान करें।

श्री शर्मा झुंझुनूं के मंड्रेला में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल की उपस्थिति में आयोजित जल संचय-जन भागीदारी-जन आंदोलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रदेश में जल जीवन मिशन में अनियमिताएं हुई, जिन पर हमारी सरकार ने ठोस कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि जेजेएम हुई गड़बड़ियों से संबंधित किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

शेखावाटी क्षेत्र को मिलेगा यमुना का पानी- मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए राम जलसेतु लिंक परियोजना से लेकर जल संरक्षण एवं संचयन के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में यमुना का पानी लाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने कोई काम नहीं किया, जबकि

हमारी सरकार ने गठन के साथ ही हरियाणा सरकार के साथ यमुना जल समझौते का एमओयू किया और इसकी डीपीआर पर काम चल रहा है। इसी तरह हमारी सरकार ने राम जलसेतु लिंक परियोजना के लिए केंद्र एवं मध्यप्रदेश सरकार के साथ एमओयू किया। इस परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में सिंचाई एवं पेयजल के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

हमनें डेढ़ साल में 13 लाख नए घरेलू नल कनेक्शन दिए- श्री शर्मा ने कहा कि हमने अब तक जितने काम किए हैं, वे काम पूर्ववर्ती सरकार अपने पूरे कार्यकाल में नहीं कर पाई। हमने अब तक जल परियोजनाओं में लगभग 13 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि गत सरकार ने डेढ़ साल में केवल साढ़े 4 हजार करोड़ रुपए खर्च किए। इसी तरह डेढ़ साल में 13 लाख नए घरेलू नल कनेक्शन दिए हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकार डेढ़ साल में मात्र पौने दो लाख कनेक्शन ही दे पाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसान कल्याण के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरूआत की है। हमने प्रदेश में किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया है। साथ ही, पशुपालन क्षेत्र को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दुग्ध उत्पादकों को सब्सिडी एवं गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण उपलब्ध करवा रही है।

पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान के लोगों से छीना नल से जल का हक- केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि हमारे देश में लगभग 4 हजार बीसीएम वर्षा जल उपलब्ध होता है, जबकि हमारी वार्षिक जल आवश्यकता लगभग 1200 बीसीएम है। जल संचयन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की शुरूआत की गई। इस अभियान में राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार और हरियाणा के प्रवासी भाई-बहन जल संचयन के लिए संरचनाओं के निर्माण में सहयोग दे रहे हैं। श्री पाटिल ने कहा कि पानी की आवश्यकता को राजस्थान से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में जल संचयन के लिए अभूतपूर्व कार्य हो रहा है और आने वाले समय में राजस्थान पूरे देश में जल आत्मनिर्भरता के लिए जाना जाएगा। राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के समय हर घर नल से जल पहुंचाने की मुहिम में गड़बड़ियां की गई। राजस्थान के लोगों से पानी का हक छीनने वाले लोगों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा।

डॉ. कर्नाटक 'राष्ट्रीय कृषि-नवाचार रत्न पुरस्कार-2025' से सम्मानित

उदयपुर। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) नई दिल्ली, द्वारा प्रायोजित दौ दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 'राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भू-स्थानिक दृष्टिकोण: एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य' का उद्घाटन 07 अक्टूबर, 2025 को संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा में हुआ। इस अवसर पर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के कुलपति डॉ. अजीत कुमार कर्नाटक को कृषि नवाचार एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान, अग्रणी नवाचारों और समर्पित सेवा के लिए प्रतिष्ठित 'राष्ट्रीय कृषि-नवाचार रत्न पुरस्कार-2025' से सम्मानित किया गया है। संगम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने बताया कि यह सम्मान डॉ. कर्नाटक द्वारा कृषि-प्रौद्योगिकियों और सतत कृषि पद्धतियों के क्षेत्र में किये गये अनुकरणीय प्रयासों से देश के कृषि क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति के लिए प्रदान किया गया है। डॉ. सक्सेना ने कहा की डॉ. कर्नाटक को शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार में 40 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ कुलपति पुरस्कार (2021), अनेको लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार, डॉ. आर.एस. परोदा पुरस्कार, डॉ. एस.एल. मिश्रा पदक, सीएचएआई मानद फैलोशिप और अमित प्रभुध मनीषी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। प्रोफेसर कर्नाटक ने द मिलेट स्टोरी नामक पुस्तक में योगदान दिया है, जिसे 2023 में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त हुई है।

डॉ. कर्नाटक ने उद्घाटन संबोधन में जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और जीएनएसएस जैसी भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों की राष्ट्रीय एवं खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इन प्रौद्योगिकियों का उत्तरदायी एवं समावेशी उपयोग न केवल निगरानी, आपदा प्रबंधन एवं संसाधन नियोजन को सशक्त बनाता है, बल्कि प्रौद्योगिकी और मानवता के बीच की खाई को भी पाटता है। यह भी साझा किया कि एमपीयूएटी में उपग्रह डेटा, ड्रोन मैपिंग और स्पैटियल एनालिटिक्स का व्यापक उपयोग फसल निगरानी, सूखा प्रबंधन और प्रिसिजन एग्रीकल्चर में किया जा रहा है। इस अवसर पर देशभर के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, नीति विशेषज्ञ एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।

कृषि के विकास से ही देश का विकास : डॉ. सोढ़ी

उदयपुर। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय (सीटीएई), उदयपुर में 23वीं एल्युमनी मिलन एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सीटीएई लाइब्रेरी में डॉ.के. एन. नाग, संस्थापक अधिष्ठाता, की मूर्ति के अनावरण से हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. आर. एस. सोढ़ी, पूर्व प्रबंध निदेशक - अमूल एवं डॉ. अजीत कुमार कर्णाटक, कुलगुरु एमयूएटी ने शिरकत की। डॉ. सोढ़ी ने डॉ. नाग के अमूल्य योगदान के बारे में बताते हुए कहा की प्रोफेसर नाग हमेशा अपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए जाने जाते रहेंगे। अनावरण के समय के बाद कोलेज के एवीपी सभागार में एलुमनाई मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अथिति डॉ. सोढ़ी, सीटीएई में कृषि अभियांत्रिकी में प्रवेश की स्वर्ण जयंती एल्युमनी भी हैं, ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में बताया कि उन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिग्री इसी संस्थान से प्राप्त की है। उन्होंने इस क्षेत्र के अनेक लाभ बताते हुए कहा कि किस प्रकार सीटीएई ने उनके करियर को दिशा दी। उन्होंने तकनीक आधारित खेती, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और मूल्य संवर्धन की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे ग्रामीण आजीविका सशक्त हो सके। डॉ. सोढी ने 'स्मार्ट और सतत ग्रामीण भारत' की अपनी परिकल्पना साझा की, जिसमें युवा अभियंता एग्री-स्टार्टअप्स, सहकारी संस्थाओं और डिजिटल कृषि के माध्यम से विकास को नई दिशा देंगे।

सम्मान समारोह कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कुलगुरु डॉ. अजीत कुमार कर्नाटक ने सीटीएई से जुड़े छत्रों के डायमंड जयंती वर्ष, स्वर्ण जयंती वर्ष एवं एवं रजत जयंती वर्ष पूर्ण करने वाले सभी एलुमनाई का साफा एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान करते हुए कहा किसी भी संस्थान के एलुमनाई उस संस्थान का पॉवर बैंक होता है और यहाँ के पूर्व छात्र तो देश विदेश में बड़े बड़े उपक्रमों को संभाले हुए हैं।

सीटीएई एलुमनाई सोसाइटी के मानद सचिव डॉ. सांवल सिंह मीना ने बताया कि एलुमनाई सोसाइटी कोलेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 12 छात्रों को नगद पुरुष्कार एवं स्मृति चिन्ह दे कर सम्मानित किया गया। कॉलेज के अधिष्ठाता डॉ. सुनील जोशी ने अवॉर्ड पाने वाले छात्र छात्रों एवं एलुमनाई को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार बोन्द्रिया द्वारा संदीप शर्मा मे. संदीप इन्टरप्राइजेस, एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित एवं पेपर प्रिंट इंडस्ट्रीज 14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (मध्यप्रदेश) से मुद्रित, सम्पादक : सुनील गंगराड़े, समन्वयक : रीतेश कोंडले. इस अंक का मूल्य रुपये 12/- वार्षिक शुल्क रुपये 600/- भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय का पंजीयन क्रं. Raj/HIN/2000/3239

कृषक जगत
संस्थापक : स्व. माणिकचन्द्र बोन्दिया - स्व. सुरेशचन्द्र गंगराड़े

अमृत जगत

मन की दुर्बलता से अधिक भयंकर और कोई पाप नहीं।

- स्वामी विवेकानन्द

किसानों की मेहनत, बाजार की बेरुखी और प्रसंस्करण की जरूरत

हर साल बरसात के मौसम में हरी सब्जियों के साथ प्याज और लहसुन की कीमतें तेज़ी से बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि आम उपभोक्ता गर्मियों के दिनों में इनका संग्रह कर लेते हैं। लेकिन यदि प्याज को उचित वातावरण और तापमान में संग्रहित नहीं किया जाए तो उसमें सड़न शुरू हो जाती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जब बाजार में आवक कम होती है तो कीमतें बढ़ती हैं और किसान उम्मीद से मंडियों का रुख करते हैं। इस साल परिदृश्य बिल्कुल उलट गया। मध्यप्रदेश के मंदसौर, नीमच और अन्य मंडियों में प्याज-लहसुन के भाव बरसात के दिनों में बढ़ने के बजाय गिर गए। दो-तीन रुपये किलो की दर पर बिकना किसानों के लिए गहरी निराशा का कारण बना। छोटे और सीमांत किसानों के लिए, जिनकी आय के साधन पहले से ही सीमित हैं, यह हालात किसी तुषारापात से कम नहीं रहे।

यह घटना नई नहीं है। इसी साल फरवरी-मार्च में टमाटर के दामों में भारी गिरावट से किसान इतने हताश हुए कि उन्होंने टमाटर को मंडियों तक ले जाने के बजाय खेतों में ही सड़ने दिया। जब भी किसी फसल की आवक मांग से अधिक हो जाती है, कीमतें गिरना स्वाभाविक है। सवाल यह है कि यदि उत्पादन अधिक हो जाए तो किसान नुकसान से कैसे बचें? चूंकि देश के 85 प्रतिशत से अधिक

किसान लघु और सीमांत श्रेणी के हैं, वे मांग का अनुमान लगाकर उत्पादन नहीं कर सकते। ऐसे में अधिशेष उत्पादन का प्रसंस्करण ही एकमात्र व्यवहारिक उपाय है।

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक देश है, लेकिन प्रसंस्करण का स्तर मात्र 2 प्रतिशत के आसपास है। यही कारण है कि हर साल करोड़ों टन उपज बर्बाद हो जाती है। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन जैसी योजनाएं शुरू की हैं। 28 फरवरी 2025 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 41 मेगा फूड पार्क, 394 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट और 536 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मंजूरी दी जा चुकी है। फिर भी, जमीनी स्तर पर पर्याप्त प्रगति न होने के कारण किसान अपनी फसल को उचित मूल्य पर बेचने से वंचित हैं।

नीतिगत प्राथमिकता की जरूरत

यह स्वीकार करना होगा कि गेहूं, धान, दलहन जैसी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था है, लेकिन फल और सब्जियों को इसके दायरे में लाना संभव नहीं है। इसलिए किसानों के हितों की रक्षा के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्राथमिकता देना ही एकमात्र रास्ता है। यदि प्रसंस्करण क्षमता मजबूत हो तो अधिशेष उत्पादन भी लाभ में बदल सकता है। इससे किसान को बेहतर मूल्य मिलेगा, उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर उत्पाद मिलेंगे और देश की खाद्य सुरक्षा भी सुदृढ़ होगी।

आज आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र और राज्य सरकारें प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना और विस्तार को उच्च प्राथमिकता दें। यदि हम फसल बर्बादी को रोकने और किसानों को लागत से ऊपर कीमत दिलाने में सफल होते हैं तो यह न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा बल्कि किसानों की आर्थिकी को स्थायी आधार भी प्रदान करेगा। प्याज और लहसुन के मौजूदा संकट ने हमें यह स्पष्ट संदेश दिया है कि केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं, बल्कि प्रसंस्करण की मजबूत व्यवस्था खड़ी करना समय की मांग है।

आमदनी में पारंपरिक खेती से आगे नहीं प्राकृतिक खेती

न ही आहार विविधता में दिलाती है खास बढ़त

● सचिन श्रीवास्तव

देश में खेती-किसानी के तरीकों को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर आधारित पारंपरिक खेती को जहां अधिक उत्पादन देने वाला माना जाता है, वहीं प्राकृतिक खेती को टिकाऊ, स्वास्थ्यकर और पर्यावरण के अनुकूल बताया जाता है। लेकिन हाल ही में किए गए एक अध्ययन ने इस बहस को नए सिरे से खोल दिया है। अध्ययन में पाया गया है कि प्राकृतिक खेती न तो आमदनी के मामले में पारंपरिक खेती से आगे है और न ही आहार विविधता में कोई खास बढ़त दिलाती है। बल्कि यह वर्ग, जाति और शिक्षा के आधार पर एक अलग सामाजिक संरचना को सामने लाती है।

यह अध्ययन 'रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डवलपमेंट की ओर से किया गया। इसमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड को शामिल किया गया। अध्ययन का उद्देश्य था- प्राकृतिक खेती का पोषण पर क्या असर है और यह व्यापक सामाजिक-आर्थिक संरचना में किस तरह शामिल होती है।

अध्ययन में पाया गया कि प्राकृतिक खेती करने वाले परिवारों के पास खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता अधिक है। वे अपने लिए भोजन का अधिकांश हिस्सा खुद पैदा कर लेते हैं और बाज़ार पर कम निर्भर रहते हैं। इसके उलट पारंपरिक किसान अधिकतर खाद्य सामग्री के लिए बाज़ार पर निर्भर रहते हैं।

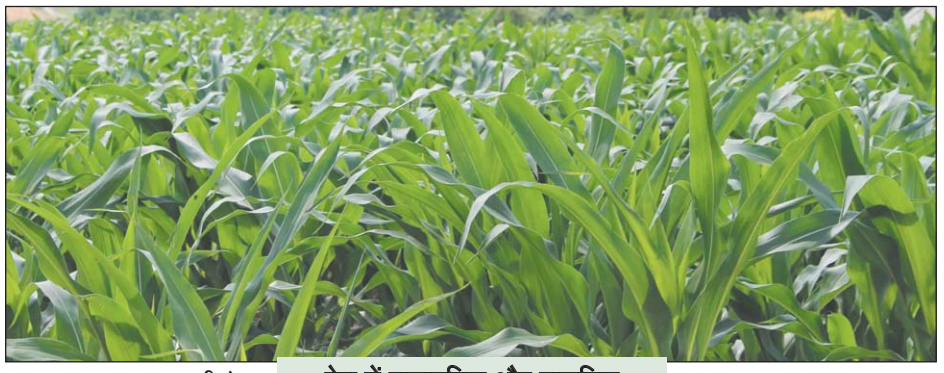

आम धारणा यह रही है कि प्राकृतिक खेती करने वाले परिवार ज्यादा पोषणयुक्त भोजन करते होंगे। लेकिन अध्ययन ने यह मिथक तोड़ दिया। दोनों ही समूहों के खानपान में कोई बड़ा अंतर नहीं मिला। यहाँ तक कि आहार विविधता पारंपरिक खेती करने वालों में थोड़ी अधिक पाई गई, क्योंकि वे बाज़ार से अलग-अलग खाद्य वस्तुएँ खरीद लेते हैं।

देश में रासायनिक और प्राकृतिक खेती के बीच जारी बहस को एक नए अध्ययन ने नया मोड़ दिया है। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि प्राकृतिक खेती न तो आय में पारंपरिक खेती से आगे है, न ही आहार विविधता में। बल्कि यह वर्ग, जाति और शिक्षा के आधार पर एक नई सामाजिक संरचना को रेखांकित करती है, जहाँ टिकाऊपन तो है, पर समानता नहीं।

प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हरित खाद, जैविक तरल खाद, वर्मी-कम्पोस्ट जैसी तकनीकों को प्राथमिकता देते हैं। यह टिकाऊ खेती का उदाहरण है। लेकिन अध्ययन में यह भी पाया गया कि पारंपरिक किसान भी अब इन तरीकों को अपनाने लगे हैं- जैसे शून्य जुताई, न्यूनतम जुताई, हरी खाद और जैव-उर्वरक का उपयोग। यानी दोनों पद्धतियों के बीच का अंतर धीरे-धीरे धुंधला होता जा रहा है।

इस बारे में एग्रोइकोलॉली विशेषज्ञ और अध्ययन दल के सदस्य अंशुमन दास प्राकृतिक और पारंपरिक खेती की तुलना कोई काले-सफेद जैसी स्थिति नहीं है। दोनों के बीच की रेखाएं धुंधली हैं। जरूरत है गहराई से समझने की कि टिकाऊ और लाभकारी खेती कैसे आगे बढ़ाई जाए।

यह है फर्क

हालांकि एक फर्क यह सामने आया कि पारंपरिक खेती करने वाले किसान कृषि के अलावा अन्य आय स्रोतों- जैसे सरकारी या निजी नौकरी पर निर्भर रहते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती करने वाले पूरी तरह कृषि पर टिके रहते हैं।

युवाओं में पारंपरिक खेती प्रचलित

अध्ययन में सामने आया कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले अधिकतर किसान उम्र में बड़े, शिक्षित और ऊंची जाति से जुड़े होते हैं। आंकड़ों के अनुसार, प्राकृतिक खेती करने वालों में 46-61 वर्ष आयु वर्ग के 38.67 प्रतिशत और 62 वर्ष से ऊपर के 18.67 प्रतिशत किसान शामिल थे। इसके उलट पारंपरिक खेती करने वाले 30-45 वर्ष आयु वर्ग के 48 प्रतिशत किसान थे, यानी पारंपरिक खेती अपेक्षाकृत युवा किसानों के बीच अधिक प्रचलित है। इसके अलावा, प्राकृतिक खेती अधिकतर पुरुषों द्वारा की जाती है, जबकि पारंपरिक खेती में महिलाओं की भागीदारी अधिक देखी गई।

सामान्य और एसटी में प्राकृतिक, ओबीसी-एससी में पारंपरिक खेती ज्यादा प्रचलित

अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह रहा कि प्राकृतिक खेती सामान्य वर्ग की जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) में अधिक प्रचलित है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अनुसूचित जातियों (एससी) में पारंपरिक खेती अधिक लोकप्रिय है। विशेषज्ञों के अनुसार, कई क्षेत्रों में आदिवासी आबादी पारंपरिक रूप से बिना रसायन वाली खेती करती रही है, इसलिए उनकी संख्या प्राकृतिक खेती में अधिक दिखती है।

उच्च शिक्षित कर रहे प्राकृतिक खेती

प्राकृतिक खेती करने वालों में उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों की संख्या भी अधिक है। इसका अर्थ है कि पढ़ाई-लिखाई का स्तर खेती की पद्धति चुनने में अहम भूमिका निभाता है। यह बात नीति-निर्माताओं के लिए खास महत्व रखती है क्योंकि शिक्षा और जागरूकता खेती में बदलाव का रास्ता खोल सकते हैं।

आय में कोई बड़ा अंतर नहीं

अध्ययन में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि प्राकृतिक और पारंपरिक खेती के बीच आय में कोई बड़ा अंतर नहीं मिला।

● हिमाचल प्रदेश में पारंपरिक किसानों की औसत सालाना आय 2,53,600 रुपए रही, जबकि प्राकृतिक किसानों की 2,52,453 रुपए।

● राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पारंपरिक किसानों की आय क्रमशः 1,60,500 रुपए और 1,13,600 रुपए रही, जबकि प्राकृतिक खेती वालों की आय 1,49,533 रुपए और 98,093 रुपए रही।

● पश्चिम बंगाल और झारखंड में दोनों वर्गों की आय लगभग समान रही।

मृदा स्वास्थ्य व टिकाऊ खेती के लिए करें जैव उर्वरकों का प्रयोग

● अनिल कुमार सिंह ● सिद्धार्थ नायक
● ऋचा सिंह ● अक्षता तोमर
● दिनेश कुमार सिंह
aksjnkvv01@gmail.com

जैव उर्वरक जीव आधारित खादें हैं। ये लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु वायुमण्डल में पहले से विद्यमान नाईट्रोजन को स्थिरीकृत कर फसल को उपलब्ध कराती हैं तथा मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस को पानी में घुलनशील अवस्था में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराती हैं। इस प्रकार रासायनिक खाद की आवश्यकता सीमित हो जाती है। जैव खाद के प्रयोग से 30 से 40 किलो ग्राम नाईट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को प्राप्त हो जाती है। जिससे फसलोत्पादन 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। अतः रासायनिक उर्वरकों को थोड़ा कम प्रयोग करके बदले में जैव उर्वरकों का प्रयोग करके फसलों की भरपूर उपज प्राप्त की जा सकती है। जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों की पूरक तो हैं ही साथ ही ये उनकी उपयोग क्षमता भी बढ़ाती हैं। फास्फोबैक्टीरिया और माइकोराइजा नामक जैव उर्वरक के प्रयोग से खेत में फास्फोरस की उपलब्धता में 20 से 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होती है साथ ही साथ फास्फोरस प्रदायी जैव उवर्रक यथा स्यूडोमोनास, बेसिलस, माइकोराइजा भूमि में उपस्थित अघुलनशील स्फुर को घुलनशील व गतिशील अवस्था में लाने का कार्य करते हैं। मुख्यतः जैव उर्वरक दो प्रकार के होते हैं - नत्रजन स्थिरीकरण जैव उर्वरक तथा फास्फोरस घोलक जैव उर्वरक। इसके अतिरिक्त पोटैशियम व जिंक प्रदायी जैव उवर्रकों के प्रयोग से पोटैशियम व जिंक की उपलब्धता बढ़ती है व खेती की लागत भी कम होती है।

फसलों के लिये राइजोबियम जैव-उर्वरक

राइजोबियम दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है। राइजोबियम जैव उर्वरक वातावरण की नाइट्रोजन को फसल के साथ सहभागिता/सहजीवी रूप में अवशोषित कर भूमि में स्थिर करते हैं। अंकुरण के उपरांत ये जीवाणु, पौधों की जड़ों में प्रविष्ट होकर छोटी-छोटी गांठों का निर्माण करते हैं और वायुमंडलीय नत्रजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इन जीवाणुओं का एक विशेष व्यवहार होता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के दलहनी फसलों के लिये अलग-अलग प्रजाति के जीवाणु आवश्यक होते हैं। जीवाणु की एक प्रजाति जो किसी फसल में जड़ ग्रथियां बनाने में सक्षम है, वह दूसरी फसल में जड़ ग्रंथियां नहीं बना सकता।

खेती में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उपज में वृद्धि तो होती है परंतु असंतुलित एवं अव्यवस्थित प्रयोग से मृदा की उर्वरता तथा संरचना पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिये रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ जैव उर्वरकों के प्रयोग की कृषि में सम्भावनायें बढ़ रही हैं। जैव उर्वरकों के प्रयोग से फसल को पोषक तत्वों की आपूर्ति होने के साथ मृदा उर्वरता भी स्थिर बनी रहती है तथा लागत भी कम लगती है। जैव उर्वरकों का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों के साथ करने से रासायनिक उर्वरकों में निहित पोषक तत्वों की क्षमता बढ़ती है जिससे फसलोत्पादन में वृद्धि होती है।

एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक

यह असहजीवी जीवाणु है जो पौधों की जड़ों की सतह में स्वतंत्र रुप से रहते हुये वायुमण्डलीय नत्रजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। ये जीवाणु कुछ विशेष पादप वृद्धि नियामक पदार्थों जैसे-जिबरेलीन का स्त्राव करते हैं जो फसल की उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही कुछ एण्टीबायोटिक रसायन उत्सर्जित करते हैं जिससे फसल में लगने वाले भूमि जन्य रोग व वायरस रोगों से फसल का बचाव होता है। एजोटोबैक्टर के उपयोग से 20-40 किग्रा नत्रजन प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष तक फसल को प्राप्त होती है।

नील हरित काई (शैवाल)

पानी की सतह पर नीले-हरे रंग की यह शैवाल, सूर्य प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाकर, वायुमण्डल की नत्रजन को स्थिरीकरण कर पौधों को उपलब्ध कराती है। इनके द्वारा 20-30 कि.ग्रा. नत्रजन प्रति हेक्टेयर तक फसल को प्राप्त होती है जिससे 10-15 प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि देखी गयी है। एक एकड़ खेत में 4 कि.ग्रा. सूखी नील-हरित शैवाल की आवश्यकता पड़ती है इसके विकास के लिये खेत में 7-8 से.मी. पानी भरा रहें।

फास्फोरस प्रदायी जैव उर्वरक (पीएसबी)

फास्फोरस प्रदायी जैव उवर्रक स्यूडोमोनास, बेसिलस, माइकोराइजा भूमि में उपस्थित अघुलनशील स्फुर को घुलनशील व गतिशील अवस्था में लाने का कार्य करते हैं। सामान्यतः स्फुर की पूर्ति हेतु प्रयोग होने वाले रासायनिक उर्वरकों जैसे-सुपर फास्फेट, डीएपी का केवल 20 प्रतिशत भाग ही घुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो पाता है। स्फुर प्रदायी जैव उर्वरक, भूमि में उपस्थित 80 प्रतिशत अघुलनशील स्फुर को घुलनशील एवं गतिशील अवस्था में लाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं जिससे पौधों की वृद्धि व विकास अच्छा होने से उत्पादन में 8-10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होती है।

जैव उर्वरक का प्रयोग कैसे करें

बीज निवेशन (बीजोपचार)- 20 से 40 कि.ग्रा. बीज के लिये राइजोबियम का एक पैकेट (200 ग्राम) पर्याप्त है इस हेतु 50-100 ग्राम गुड़/शक्कर को 500 मिली पानी में घोल बनाकर उसे गर्म करते हैं व ठंडा कर इसमें जैव उर्वरक को घोलकर, बीज के साथ मिलायें। जब राइजोबियम व पीएसबी को एक साथ उपयोग करना हो तब राइजोबियम का एक पैकेट व पीएसबी के दो पैकेट उपयोग करें। बीज को छाया में सुखाकर उसी दिन बुवाई कार्य करें।

जड़ उपचार - जैविक खाद का प्रयोग जड़ोपचार हेतु रोपाई वाली फसलों में करते हैं। 4 किलोग्राम जैव उर्वरक का 20 -25 लीटर पानी में घोल बनायें। एक हेक्टेयर के लिये पर्याप्त पौध की जड़ों को 25-30 मिनट तक उपरोक्त घोल में डुबोकर रखें। उपचारित पौध को छाया में रखें तथा यथाशीघ्र रोपाई कर दें।

मृदा उपचार - एक हेक्टेयर भूमि के लिये 200 ग्राम वाले 25 पैकेट जैव उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। 50 किलोग्राम मिट्टी या 50 किलोग्राम कम्पोस्ट खाद में 5 किलोग्राम जैव उर्वरक को अच्छी तरह मिलायें। इस मिश्रण को एक हैक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई के समय या बुआई से 24 घंटे पहले समान रूप से छिड़कें। इसे बुआई के समय कूड़ों में भी डाल सकते हैं।

जैव उर्वरकों के उपयोग में सावधानियां

● नाइट्रोजन जैव उर्वरकों के साथ फास्फोबैक्टीरिया का प्रयोग अत्यन्त लाभकारी है। प्रत्येक दलहनी फसल के लिये अलग राइजोबियम कल्चर तैयार किये जाते हैं। अतः दलहनी फसल के अनुरूप ही राइजोबियम कल्चर क्रय कर प्रयोग करें।

● जैव उर्वरकों को धूप में कभी न रखें, यदि इसे कुछ दिनों के लिये रखना हो तो मिट्टी के घड़े का प्रयोग बहुत अच्छा है। ● फसल विशेष के अनुसार ही जैव उर्वरक का चुनाव करें। ● रासायनिक खाद तथा कीटनाशक दवाईयों से जैव उर्वरक को दूर रखें तथा इनका एक साथ प्रयोग भी न करें। ● जब बीज को फफूंदनाशक दवा से भी उपचारित करना हो तो पहले फफूंदनाशक से और फिर जैव उर्वरक से उपचारित करें। ● जैव उर्वरकों की अच्छी कार्यप्रणाली के लिये 20-35 सेण्टीग्रेड तापमान अनुकूल रहता है। परिवहन के दौरान इन्हें धूप से बचायें साथ ही पर्याप्त नमी होने पर ही खेत में उपयोग करें। ● जैव उर्वरकों का स्वजीवन 6 माह का होता है अतः प्रभाव समाप्ति अवधि के पूर्व ही फसल अनुसार उपयोग करें। ● अम्लीय भूमियों में प्रयोग के लिये उपचारित बीजों पर चूना, डोलोमाइट अथवा सुपर फास्फेट का लेप चढ़ा दें। क्षारीय भूमि में बीजों पर जिप्सम की पर्त चढ़कर बोनी करें।

पोटैशियम प्रदायी जैव उर्वरक (केएसबी)

पोटैशियम प्रदायी जैव उवर्रक भूमि में उपस्थित अघुलनशील पोटैशियम को घुलनशील अवस्था में लाने का कार्य करते हैं। सामान्यतः पोटैशियम की पूर्ति हेतु प्रयोग होने वाले रासायनिक उर्वरकों जैसे- म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी), सल्फेट ऑफ पोटाश (एसओपी) का 50 से 60 प्रतिशत भाग ही घुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो पाता है। पोटैशियम प्रदायी जैव उर्वरक, भूमि में उपस्थित 40 से 50 प्रतिशत अघुलनशील पोटैशियम को घुलनशील अवस्था में लाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं जिससे पौधों की वृद्धि व विकास अच्छा होने से उत्पादन में 20-25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होती है।

जिंक प्रदायी जैव उर्वरक (जेडएसबी)

जिंक प्रदायी जैव उवर्रक भूमि में उपस्थित अघुलनशील जिंक को घुलनशील व गतिशील अवस्था में लाने का कार्य करते हैं। सामान्यतः जिंक की पूर्ति हेतु प्रयोग होने वाले रासायनिक उर्वरकों जैसे- जिंक सल्फेट का 5 से 10 प्रतिशत भाग ही घुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो पाता है। जिंक प्रदायी जैव उर्वरक, भूमि में उपस्थित अघुलनशील जिंक को घुलनशील अवस्था में लाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं जिससे पौधों की वृद्धि व विकास अच्छा होने से उत्पादन में 10-15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होती है।

जैव उर्वरकों के प्रयोग से लाभ

● ये अन्य रासायनिक उर्वरकों से सस्ते होते हैं जिससे फसल उत्पादन की लागत घटती है। ● जैव उर्वरकों के प्रयोग से नाईट्रोजन, घुलनशील फास्फोरस, पोटैशियम व जिंक आदि की फसल के लिये उपलब्धता बढ़ती है। ● इससे रासायनिक खाद का प्रयोग कम हो जाता है जिससे भूमि की मृदा संरचना अच्छी बनी रहती है। ● जैव उर्वरक से पौधों में वृद्धिकारक हारमोन्स उत्पन्न होते हैं जिनसे उनकी बढ़वार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ● जैव उर्वरक से फसल में मृदाजन्य रोग नहीं होते हैं। ● जैविक खाद से खेत में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती है। ● जैविक खाद से मृदा तथा पर्यावरण सुरक्षित रहता है। ● अम्लीय और क्षारीय भूमियों का सुधार होता है। ● मृदा में कार्बनिक पदार्थों तथा अन्य पौध विकास वर्धक रसायनों जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलीन, फाइरीडोक्सीन, इण्डोल एसिटिक एसिड इत्यादि के मात्रा में वृद्धि हो जाती है।

विभिन्न जैव उर्वरक, मात्रा एवं संस्तुत प्रयोग विधि

जैव उर्वरक	उपयुक्त फसलें	संस्तुत प्रयोग विधि	आवश्यक मात्रा
राइजोबियम	सभी दलहनी फसलों के लिये	बीजोपचार	200 ग्राम प्रति 10-15 किग्रा बीज
एजोटोबैक्टर	दलहनी फसलों को छोड़कर अन्य सभी फसलों के लिये	बीजोपचार, जड़ उपचार, व मृदा उपचार	200 ग्राम प्रति 10-15 किग्रा बीज या 5 किग्रा प्रति हेक्टेयर
एसिटोबैक्टर	केवल गन्ने के लिये	बीजोपचार, व मृदा उपचार	200 ग्राम प्रति 10-15 किग्रा बीज या 5 किग्रा प्रति हेक्टेयर
एजोस्पिरिलम	दलहनी फसलों को छोड़कर अन्य सभी फसलों के लिये, गन्ने के लिये विशेष उपयोगी	बीजोपचार, जड़ उपचार,व मृदा उपचार	200 ग्राम प्रति 10-15 किग्रा बीज या 5 किग्रा प्रति हेक्टेयर
फास्फोबैक्टीरिया	सभी फसलों के लिये	बीजोपचार, जड़ उपचार व मृदा उपचार	200 ग्राम प्रति 10-15 किग्रा बीज या 5 किग्रा प्रति हेक्टेयर
माइकोराइजा	सभी फसलों के लिये	मृदा उपचार	5-7 किग्रा प्रति हेक्टेयर
पोटैशियम घोलक जीवाणु	सभी फसलों के लिये	मृदा उपचार	2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर
जिंक घोलक जीवाणु	सभी फसलों के लिये व मृदा उपचार	बीजोपचार, जड़ उपचार	100 मिली प्रति 10-15 किग्रा बीज या 1-2 किग्रा प्रति हेक्टेयर
नील हरित शैवाल	मृदा उपचार धान फसल के लिये		10-12 किग्रा प्रति हेक्टेयर

विभिन्न फसलों हेतु उपयोगी राइजोबियम प्रजातियां

राइजोबियम की प्रजाति	फसल
राइजोबियम लेग्युमिनोसेरम	मटर, मसूर एवं खेसारी
राइजोबियम फेसियोलाई	राजमा
राइजोबियम ट्राईफोलाई	बरसीम
राइजोबियम ल्यूपिनी ल्यूपिन	वार्षिक एवं बहुवार्षिक
राइजोबियम मिलिलोटाई	लूर्सन, मेथी एवं स्वीट क्लोवर
राइजोबियम स्पेसीज	लोबिया, चना, मोथ, कुल्थी

राइजोबियम प्रजातियों द्वारा दलहनी फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण की मात्रा

दलहनी फसलें	नत्रजन स्थिरीकरण (किग्रा/हे.)
अरहर	70-200
ढेंचा	100-120
उड़द-मूंग	70-90
लोबिया	80-85
सोयाबीन	65-120
चना	80-100
मटर	52-77
मसूर	90-100

फलों में पोषक तत्वों का मूल्यांकन

● उपेन्द्र यादव ● हंस राज वर्मा
शोध छात्र, फल विज्ञान विभाग
● विवेक यादव
एमएससी छात्र, फल विज्ञान विभाग
चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर (उप्र)
upendray123123@gmail.com

फलों के पौधों के लिए अपनाई जाने वाली प्रबंधन प्रणाली, विशेषकर पोषक तत्वों के संबंध में, खेत की फसलों के लिए अपनाई गई प्रबंधन प्रणाली से काफी भिन्न होती है। पेड़ के आकार के आधार पर प्रबंधन प्रणाली में बदलाव रोपण के 3-4 साल बाद शुरू किया जा सकता है। फूल आने और फल लगने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है,

साथ ही पेड़ों को बढ़ने और अगले वर्षों में उच्च पैदावार देने के लिए पर्याप्त शक्ति बनाए रखने के लिए भी आवश्यक होता है। लंबे समय तक पेड़ों की उत्पादकता बनाए रखने और पौधों की उत्पादन क्षमता की स्थिरता बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों का उपयोग मिट्टी में पोषक तत्वों की वास्तविक आवश्यकता और उपलब्धता पर आधारित होना चाहिए। पौधों में पोषक तत्वों का किफायती ढंग से सही समय पर सही मात्रा में उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि पौधों द्वारा पोषक तत्वों को कम से कम नुकसान के साथ कुशलतापूर्वक ग्रहण किया जा सके। फलों के पौधों की पोषक तत्वों की आवश्यकता के आकलन का उद्देश्य पौधों में खनिज पोषक तत्वों के स्तर को वांछित सीमा में बनाए रखना है ताकि पेड़ों की वृद्धि, विकास और वांछित फलन प्राप्त हो सके।

मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक

- वनस्पति आवरण का प्रकार; जैसे दलहनी फसलों के साथ नाइट्रोजन अधिक होता है
- खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग
- मृदा संशोधन का अनुप्रयोग
- मिट्टी की विरासत स्थिति

पत्ती में पोषक तत्वों की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक

- उर्वरक का प्रयोग
- वनस्पति आवरण का प्रकार; जैसे फलियां कवर के साथ नाइट्रोजन अधिक हो सकता है।
- पेड़ में निहित कारक; आनुवंशिक संरचना, पौधे की उम्र, नमूना लेने का समय; वार्षिक (मौसमी) भिन्नता, पत्तियों की आयु, पत्तियों की स्थिति।

पत्तियों के नमूने

फलों के पेड़ों की पोषण संबंधी आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए पत्ती विश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है। पत्ती में पोषक तत्वों का उचित विश्लेषण पत्तियों के ऊतकों का विश्लेषण करके प्राप्त की जा सकता है। इसके बाद पोषक तत्वों की पूर्ति उनकी कमी इष्टतम मानदंडों के अनुसार पौधो को प्रदान की जाती है।

फलों की फसलों के लिए पौधों के ऊतकों के नमूने के दिशा निर्देश

फल	सूचकांक ऊतक	वृद्धि चरण
अंगूर	आधार से 5वाँ डंठल	उपज पूर्वानुमान के लिए कली विभेदन चरण, डंठल
केला	शीर्ष से तीसरी खुली पत्ती का डंठल	कली विभेदन चरण
शरीफा	शीर्ष से पाँचवाँ पत्ता	नई वृद्धि के 2 महीने बाद
अंजीर	पूरी तरह से विस्तारित पत्तियां, मध्य शूट वर्तमान विकास	जुलाई-अगस्त
अमरूद	हाल ही में पकी पत्तियों का तीसरा जोड़ा	खिलने की अवस्था
नींबू	नई फ्लश से 3 से 5 महीने पुरानी पत्ती, अंकुर का पहला पत्ता	जून
आम	पत्तियां डंठल	अंकुर के बीच से 4 से 7 महीने पुरानी पत्तियाँ
अनार	शीर्ष से आठवीं पत्ती	कली विभेदन, फरवरी की फसल के लिए अप्रैल में और जून की फसल के लिए अगस्त में
पपीता	शीर्ष से छठा डंठल	रोपण के 6 महीने बाद
फालसा	शीर्ष से चौथा पत्ता	छंटाई के एक महीने बाद
बेर	द्वितीयक या तृतीयक प्ररोह के शीर्ष से 16वीं पत्ती	छंटाई के दो महीने बाद
चीकू	शीर्ष से 10वीं पत्ती	सितम्बर

बागवानी फसलों के लिए इष्टतम मानदंड

पोषक तत्व	अंगूर (थॉम्पसन बीजरहित)	आम (तोतापुरी)	कागज़ी नींबू	अनार	केला (रोबूस्टा)
नाइट्रोजन (%)	0.87-1.61	0.84-1.53	1.53-2.10	0.91-1.66	1.67-3.43
फास्फोरस (%)	0.29-0.65	0.64-0.15	0.10-0.15	0.12-0.18	0.12-0.21
पोटेशियम (%)	2.0-3.0	0.52-1.10	0.96-1.66	0.61-1.59	2.28-4.14
कैल्शियम (%)	0.98-1.36	1.97-3.20	3.05-3.43	0.77-2.00	0.48-1.70
मैग्नीशियम (%)	0.63-1.10	0.40-0.65	0.40-0.60	0.16-0.42	0.33-0.58
सल्फर (%)	0.09-0.13	0.15-0.22	0.25-0.29	0.16-0.26	0.03-0.18
आयरन (पीपीएम)	54-80	48-86	117-194	71-214	53-196
मैंगनीज (पीपीएम)	42-209	57-174	21-63	29-89	112-417
जिंक (पीपीएम)	30-88	25-33	25-50	14-72	8-38
कॉपर (पीपीएम)	5-10	3.1-8.0	8.7-14.8	29-72	10-32

मिट्टी की सेहत बचाएं, खेत की उपज बढ़ाएं

● श्रीयांशु राठौर, shriyanshurathore2002@gmail.com

मिट्टी बचेगी तभी खेती टिकेगी

किसानों भाइयों और बहनों,

हमारी खेती की असली ताकत मिट्टी है। मिट्टी नहीं तो अनाज नहीं। लेकिन आज लगातार ज्यादा जुताई, रासायनिक खाद का अत्यधिक उपयोग, पेड़ों की कटाई और बारिश का बहाव हमारी मिट्टी को खराब कर रहा है।

जिस जमीन से हम रोज़ी-रोटी कमाते हैं, वही अगर कमजोर हो जाए, तो हमारी खेती भी कमजोर हो जाएगी। इसीलिए आज सबसे जरूरी है - मृदा संरक्षण यानी मिट्टी की रक्षा।

मिट्टी बिगाड़ने वाले काम

- बार-बार खेत को जोतना
- सिर्फ एक ही फसल बार-बार लगाना
- जरूरत से ज्यादा रासायनिक खाद डालना
- पेड़-पौधे काट देना
- बिना योजना के सिंचाई करना

मिट्टी बचाने के आसान उपाय

फसल चक्र अपनाएं: गेहूं के बाद दलहनी फसलें (जैसे मूंग, उड़द) लगाएं।

इससे मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ता है।

जैविक खाद डालें: गोबर की खाद, कंपोस्ट या वर्मी कम्पोस्ट से मिट्टी की ताकत बढ़ती है।

पौधे लगाएं (वनरोपण): खेत की मेड़ों पर पेड़ और झाड़ियाँ लगाएं। इससे मिट्टी बहती नहीं है।

सीढ़ीनुमा खेती : पहाड़ी या ढलान वाले इलाकों में यह तरीका बहुत कारगर है।

कंटूर नाली बनाएं: पानी को सीधे नीचे बहने से रोकें। इससे मिट्टी नहीं बहती और जल भी बचता है।

मिट्टी की जांच कराएं: 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' के तहत सरकार मुफ्त में मिट्टी की जांच करवाती है।

सरकार से मदद कैसे लें?

कृषि विभाग से संपर्क करें - अपने जिले के कृषि अधिकारी से सलाह लें।

कृषि विज्ञान केंद्र - हर जिले में मौजूद हैं। वहां से मृदा संरक्षण पर प्रशिक्षण मिल सकता है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना - इस योजना के तहत हर किसान को बताया जाता है कि उसकी जमीन में कौन-कौन से पोषक तत्व कम हैं।

लेखक की बात

मिट्टी हमारी माँ है। माँ को बीमार नहीं होने देना है। अगर आज से हम मृदा संरक्षण शुरू करें, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ ज़मीन मिलेगी।

तो आइए, हम सब मिलकर मिट्टी की रक्षा करें और खेती को समृद्ध बनाएं।

पोल्ट्री में कूड़ा प्रबंधन

कूड़ा प्रबंधन टिकाऊ पोल्ट्री उत्पादन की आधारशिला है, जिसका सीधा प्रभाव पक्षियों के स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा और सामुदायिक स्वीकृति पर पड़ता है। पोल्ट्री उत्पादकों के सामने आने वाली कई चुनौतियों में से, मक्खियों का प्रकोप और लगातार आने वाली दुर्गंध को नियंत्रित करना सबसे कठिन है। ये समस्याएँ न केवल फार्म की स्वच्छता को प्रभावित करती हैं, बल्कि रोग संचरण, नियामक जाँच और पड़ोसी समुदायों के साथ तनावपूर्ण संबंधों का जोखिम भी पैदा करती हैं। हालाँकि भौतिक और रासायनिक हस्तक्षेपों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन उनकी सीमाएँ तेज़ी से स्पष्ट होती जा रही हैं, जिससे अधिक समग्र समाधानों की आवश्यकता बढ़ रही है।

समस्या का पैमाना

लेयर फ़ार्म में, खाद लंबे समय तक जमा होती रहती है। उच्च कार्बनिक तत्व, नमी और गर्मी के साथ मिलकर, सूक्ष्मजीवों के अपघटन के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करते हैं। इस अपघटन से अमोनिया और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs) निकलते हैं, जिससे विशिष्ट गंध उत्पन्न होती है। साथ ही, खाद मक्खियों, विशेष रूप से घरेलू मक्खी (मस्का डोमेस्टिका) के लिए प्रजनन स्थल बन जाती है, जो नम कूड़े में पनपती है।

ये मक्खियाँ केवल एक उपद्रव ही नहीं हैं- ये साल्मोनेला, ई. कोलाई और कैम्पिलोबैक्टर जैसे रोगजनकों के लिए यांत्रिक वाहक का काम करती हैं। इस बीच, गंध उत्सर्जन न केवल फ़ार्म की हवा की गुणवत्ता को कम करता है, बल्कि आस-पास के समुदायों की शिकायतों को भी बढ़ाता है, जो अक्सर नियामक चुनौतियों का कारण बनता है।

हस्तक्षेप और उनकी सीमाएँ

उत्पादक लंबे समय से भौतिक हस्तक्षेपों पर निर्भर रहे हैं, जैसे-

- प्रजनन सामग्री को कम करने के लिए बार-बार खाद हटाना।
- गंध को दूर करने और कूड़े को सूखा रखने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम।
- यांत्रिक टर्नर का उपयोग करके कूड़े को सुखाना और वातन करना।
- वयस्क मक्खियों की आबादी को कम करने के लिए जाल।

हालाँकि ये उपाय अस्थायी राहत प्रदान करते हैं, लेकिन वास्तविक परिस्थितियों में ये अक्सर विफल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए-

- बार-बार खाद हटाना श्रमसाध्य और महंगा है, खासकर बड़े पैमाने पर संचालन में।
- वेंटिलेशन गंध को दूर करता है लेकिन इसके स्रोत को खत्म नहीं करता है।
- यांत्रिक सुखाने का काम असंगत है, खासकर आर्द्र या बरसात के मौसम में।
- जाल और जाल वयस्कों की संख्या को कम करते हैं लेकिन मूल कारण कूड़े में मक्खियों का प्रजनन को संबोधित नहीं करते हैं।

रासायनिक हस्तक्षेप और उनकी कमियाँ

कीटनाशक, लार्वानाशक, कीटाणुनाशक और कूड़े में सुधार जैसे रासायनिक हस्तक्षेप, पोल्ट्री अपशिष्ट प्रबंधन में आम उपकरण हैं। हालाँकि, उनकी सीमाएँ तेजी से पहचानी जा रही हैं-

- मक्खियों की आबादी में कीटनाशक प्रतिरोध तेज़ी से विकसित होता है, जिससे समय के साथ उनकी प्रभावशीलता कम होती जाती है।
- रासायनिक अवशेष कूड़े को दूषित कर सकते हैं, जिससे फसल के उपयोग या खाद बनाने में चिंताएँ पैदा हो सकती हैं।
- फिटकरी या चूने जैसे अमोनिया-बाध्यकारी रसायन अस्थायी रूप से गंध को कम कर सकते हैं, लेकिन इन्हें बार-बार इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है, जिससे लागत बढ़ जाती है।
- रसायनों पर अत्यधिक निर्भरता कूड़े के सूक्ष्मजीवी संतुलन को बिगाड़ सकती है, जिससे कभी-कभी गंध की उत्पत्ति और भी बदतर हो जाती है।

इसके अलावा, रासायनिक अवशेषों और स्थायित्व से जुड़ी पर्यावरणीय और उपभोक्ता चिंताएँ, खेतों को इन तरीकों पर पूरी तरह निर्भर रहने से दूर जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

आवर्ती मक्खी चक्र : लार्वा नियंत्रण क्यों महत्वपूर्ण है

मक्खियाँ अपने तेज़ और आवर्ती जीवन चक्र के कारण लगातार जीवित रहती हैं। एक घरेलू मक्खी नम खाद पर सैकड़ों अंडे दे सकती है, जो 24 घंटे के भीतर लार्वा (मैगॉट्स) में बदल जाते हैं। ये लार्वा अनुकूल परिस्थितियों में 10 दिनों से भी कम समय में प्यूपा बन जाते हैं और वयस्क बन जाते हैं। जब तक कूड़ा नमी, गर्मी और पोषक तत्व प्रदान करता रहता है, यह चक्र अनवरत चलता रहता है।

केवल वयस्क मक्खियों को लक्षित करना एक अल्पकालिक रणनीति है। यदि वयस्कों को भी नष्ट कर दिया जाए, तो कुछ ही दिनों में नई पीढ़ियाँ उभर आती हैं, जिससे संक्रमण फिर से फैल जाता है। मक्खियों को नियंत्रित करने का एकमात्र स्थायी तरीका लार्वा अवस्था में ही इस चक्र को तोड़ना है। कूड़े को सुखाने, पोषक तत्वों को स्थिर करने, या लार्वा के विकास को सीधे दबाने वाले हस्तक्षेप मक्खियों की आबादी को उनके स्रोत पर ही नाटकीय रूप से कम कर सकते हैं। लार्वा पर ध्यान केंद्रित करके, उत्पादक जाल और कीटनाशकों से वयस्क मक्खियों का लगातार पीछा करने के बजाय भविष्य में होने वाले प्रकोपों को रोक सकते हैं।

वर्तमान दृष्टिकोण अपर्याप्त क्यों हैं?

मक्खियों और दुर्गंध की समस्याओं का बने रहना एक महत्वपूर्ण बात को उजागर करता है- भौतिक और रासायनिक हस्तक्षेप मुख्यतः लक्षणों को संबोधित करते हैं, कारणों को नहीं। मक्खियाँ इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि गोबर पोषक तत्वों से भरपूर और उनके जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नम रहता है। दुर्गंध इसलिए बनी रहती है क्योंकि यूरिक एसिड और प्रोटीन का सूक्ष्मजीवी विघटन अनियंत्रित रूप से जारी रहता है। जब तक कूड़ा जैविक रूप से अस्थिर रहेगा, बार-बार हस्तक्षेप के बावजूद ये समस्याएँ फिर से उभरती रहेंगी।

सतत प्रबंधन की ओर बढ़ना

वर्तमान रणनीतियों की सीमाएँ एकीकृत, जीव-केंद्रित दृष्टिकोणों की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं जो खाद को स्रोत पर ही स्थिर कर सकें। कूड़े में सूक्ष्मजीवी गतिविधि और पोषक तत्वों की गतिशीलता को संशोधित करके, यह संभव हो जाता है-

- अमोनिया उत्सर्जन और गंध निर्माण को कम करना।
- मक्खी प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियों को सीमित करना।
- कूड़े के मूल्य को एक सुरक्षित, पोषक तत्वों से भरपूर जैविक उर्वरक के रूप में बेहतर बनाना।

ऐसे दृष्टिकोण न केवल दीर्घकालिक परिणाम प्रदान करते हैं, बल्कि पोल्ट्री उद्योग के स्थायित्व, जैव सुरक्षा और चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं की ओर बढ़ने के प्रयासों के अनुरूप भी हैं।

कृषक जगत राष्ट्रीय कृषि अखबार भोपाल-जयपुर-रायपुर द्वारा प्रकाशित फसल पुस्तक श्रृंखला

जैविक खेती समृद्ध कृषक | भण्डारण के वैज्ञानिक तरीके | एकीकृत कीट प्रबंधन | मधुमक्खी पालन | जायद फसलें | सरसों | मसाला फसलें
सदाबहार खेती | चना | मृदा उर्वरता मैनुअल | खेती के उन्नत तरीके (खरीफ फसल) | खेती के उन्नत तरीके (रबी फसलें) | सोयाबीन अनुसंधान तकनीक | बाजरा की वैज्ञानित खेती
रबी तिलहनी फसलें अलसी, कुसुम | मसूर, मटर एवं मोठ की उत्पादन तकनीक | लघु धान्य फसलों की उत्पादन तकनीक | कौशल विकास दिग्दर्शिका | गेहूं उत्पादन तकनीक | एकीकृत पौध पोषक तत्व प्रबंधन | पौध संरक्षण (खरीफ-रबी फसल सहित)

नाम ..... ग्राम.....
पोस्ट ..... तह. ..... जिला.....
फोन/मोबा. .....कुल राशि.....
ऑर्डर की गई प्रतियों की संख्या/संलग्न ड्राफ्ट नं. .....
मनी ऑर्डर क्र. ..... वी.पी. भेजें।

नोट : कृपया ड्राफ्ट या मनीऑर्डर कृषक जगत भोपाल के नाम नीचे लिखे पते पर भेजें

प्रधान कार्यालय : 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल-462011
फोन: 0755-4248100,2554864, मो. : 9826255861
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास इंदौर
मो. : 09826021837

समस्या -समाधान

ड्रिप

समस्या : ड्रिप सिंचाई क्या है?

समाधान : ड्रिप सिंचाई को ट्रिकल अथवा सूक्ष्म सिंचाई भी कहा जाता है और यह सर्वाधिक प्रभावी तकनीक है जिसमें फसल उत्पादन के लिए जल, उर्वरकों तथा अन्य पोषक तत्वों का कहीं अधिक प्रभावी उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य सिद्धान्त खेत में प्लास्टिक पाइप पर लगाये गये इमीटर्स की मदद से यथा संभव पौधे की जड़ के निकट जल तथा निवेशों का धीरे-धीरे, निरन्तर और बार-बार प्रयोग करना है।

लेजर लैण्ड लेवलिंग

समस्या : लेजर लैण्ड लेवलिंग के क्या लाभ हैं?

समाधान: जल अनुप्रयोग प्रभावशीलता में सुधार लाने और फसल की पैदावार को बढ़ाने में लेजर लैण्ड लेवलिंग एक आदर्श हस्तक्षेप है। वर्ष 2008 के दौरान कृषि विभाग के योजना तथा मूल्यांकन सेल द्वारा किए गए प्रभाव आकलन अध्ययन में इसके निम्नलिखित प्रभाव पाए गए:-सिंचाई के समय में 25.1 से 32.1 प्रतिशत तक की बचत। सिंचित क्षेत्रफल में 34.5 से 42.0 प्रतिशत तक की वृद्धि। फसल पैदावार में 10.7 से 12.9 प्रतिशत तक का सुधार। फार्म संवर्धन योग्य बंजर भूमि में 2.10 प्रतिशत तक की कमी। फसल को बेहतर ढंग से खड़े होने, एक समान नमी उपलब्धता और बढ़ी हुई उर्वरक उपयोग प्रभावशीलता की सुविधा।

निवेदन

समस्या-समाधान स्तंभ में पाठकों से निवेदन है कि अपनी खेती-किसानी संबंधी समस्या कृषि विशेषज्ञों से निराकरण करने हेतु वाट्सएप पर भेजें. एक बार में केवल एक प्रमुख समस्या ही वाट्सएप पर लिखकर भेजें. वाट्सएप हेल्पलाइन नं. 6262166222.

समस्या-समाधान
कृषक जगत 14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स,
महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.)
फोन-0755-4248100,2554864

सरसों

समस्या : सरसों की फसल में माहो के प्रकोप को कैसे नियंत्रित करें?

समाधान: सरसों में चेपा या माहू का प्रकोप दिसम्बर से जनवरी के माह में बादल वाले मौसम में अधिक होता है। इससे बचाव के लिए सरसों की बुआई मध्य अक्टूबर तक अवश्य करें। इससे फसल पर चेपा का कम प्रकोप होगा। यदि फिर भी प्रकोप होता है तो मैलाथियान दवा की एक लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 400-600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

पपीता

समस्या : पपीते के बाग में नर-मादा पौधों को कैसे पहचाना जा सकता है?

समाधान: फूल निकलने से पहले नर और मादा पौधों को पहचाना नहीं जा सकता है। फूल निकलने के बाद पहचान यह है कि नर फूल लम्बी-लम्बी टहनियों (फूल वाली) के ऊपर अनेक संख्या में गुथे होते हैं। इस प्रकार की फूलों वाली टहनियां पत्तियां हैं। मादा फूल पत्तियों की काखों से अकेला-अकेला निकलता हैं और इसमें फल नुमा फूला हुआ भाग होता है।

पशु बीमा

समस्या : मेरे पास लगभग 35 पशु हैं,

बीमा कराना चाहता हूं, मार्गदर्शन दें।

समाधान: पशुओं का बीमा 4 सरकारी बीमा कंपनियां नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, दिनयू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी तथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी करती है। जब भी कोई पशुपालक सरकारी योजना के अंतर्गत पशु खरीदता है तो उस पशु का बीमा उसी समय किया जाता है परंतु यदि कोई पशुपालक बगैर योजना के पशु रखता है तब उसे क्षेत्र के पशुचिकित्सक से पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाकर बीमा कंपनी में जमा कराना पड़ता है। पशु की कीमत का लगभग 3 प्रतिशत प्रीमियम कंपनी लेकर पशु का एक साल के लिए बीमा कर देती है। पशु के कान में कंपनी का टेग डाल दिया जाता है। पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को बीमा कंपनी में सूचना देनी होती है तथा पशु चिकित्सक से पोस्टमार्ट्म कराना होता है। दावा करने के बाद पशुपालक को बीमित राशि का भुगतान हो जाता है।

मूली

समस्या : सालभर क्या मूली की खेती करना संभव है, तकनीकी बतायें?

समाधान: विभिन्न मौसम में उगाई जाने

वाली मूली की उन्नत किस्में, किस्म, बुआई का समय फसल तैयार होने का समय, उपज, पूसा देसी अगस्त के मध्य से अक्टूबर मध्य तक, मध्य सितम्बर से मध्य दिसम्बर तक, पूसा मृदुला सितम्बर के प्रथम पखवाड़े से मध्य नवम्बर तक अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े से जनवरी के पहले खवाड़े तक, जेपनीज़ व्हाइट, पूसा स्वेता, पूसा जामुनी, पूसा गुलाबी दिसम्बर के दूसरे पखवाड़े से फरवरी तक मध्य फरवरी से अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक, पूसा चेतकी अप्रैल के पहले सप्ताह से मध्य अगस्त तक मई के पहले पखवाड़े से सितम्बर के दूसरे पखवाड़े तक इन किस्मों को सालभर लगाया जा सकता है।

कृषक जगत
बागवानी सीरीज

साग-सब्जी उत्पादन उन्नत तकनीक	सब्जियों में पौध संरक्षण	मशरूम एक लाभ अनेक	मिर्च की उन्नत खेती	केला उत्पादन	गुलाब बहुरंगी संशोधित संस्करण
रु. 95	रु. 75	रु. 45	रु. 55	रु. 70	रु. 75
कोड : 016	कोड : 017	कोड : 019	कोड : 020	कोड : 025	कोड : 027

पपीता	अदरक	फलों की खेती	सजाएं फूलों से बगिया	घर की बगिया
रु. 55	रु. 55	रु. 75	रु. 65	रु. 95
कोड : 031	कोड : 032	कोड : 040	कोड : 041	कोड : 050

डाक द्वारा मंगवाने हेतु निम्नलिखित जानकारी के साथ हमारे पते पर ड्राफ्ट/मनीऑर्डर के साथ ऑर्डर कीजिए . किताब कोड नं. पर ✔ निशान लगाएं

016 ☐ 017 ☐ 019 ☐ 020 ☐ 025 ☐ 027 ☐ 031 ☐ 032 ☐ 034 ☐ 040 ☐ 041 ☐ 050 ☐

नाम _____
ग्राम _____ पोस्ट _____ तह. _____
जिला _____ फोन/मोबा. _____
कुल राशि _____ ऑर्डर की गई प्रतियों की संख्या _____
संलग्न ड्राफ्ट नं. _____ मनी आर्डर रसीद क्र. _____ वी.पी. भेजें ☐

संस्थाओं द्वारा अधिक संख्या में प्रतियां खरीदने पर आकर्षक छूट. अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें.

कृपया ड्राफ्ट या मनीआर्डर कृषक जगत भोपाल के नाम
14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल - 462011
फोन : 0755-4248100, 2554864, मो.: 9826255861, Email-info@krishakjagat.org
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास, इंदौर (म.प्र.) मो. : 9826021837

स्वास्थ्य

अक्षर नहीं पहचान पाना आंखों में रोग का संकेत

बच्चा अगर पढ़ने के दौरान अक्षरों को पहचानने में बार–बार गलती करता है तो इसके लिये उसकी आंखें जिम्मेवार हो सकती हैं। एक नए अध्ययन से पता चला है कि आंखों में खराबी के कारण अक्षरों को पहचानने में समस्या आती है।

शोधकर्ताओं ने कहा कि जब कोई बच्चा अक्षरों को सही–सही नहीं पहचान पाता तब इसको उसकी सीखने–समझने की क्षमता की कमी समझा जाता है। यह भी माना जाता है कि पढ़ने में दिलचस्पी नहीं होने के कारण वह ऐसा करता है। पर अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि यह समस्या केवल दिमागी विकास की कमी या पढ़ाने में रुचि न लेने की आदत का नतीजा नहीं है। शोधकर्ताओं ने पाया कि अक्षर पहचानने में होने वाली परेशानी में मस्तिष्क की भूमिका ही नहीं होती। इसके लिए आंखें जिम्मेदार होती हैं, जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना उसको मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। जब आंखें गलत प्रतिबिंब बनाती हैं तब मस्तिष्क वस्तु का वास्तविक पहचान नहीं कर पाता।

वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसान की दोनों आंखों की कोशिकाओं की बनावट भी अलग–अलग होती है। आम तौर पर इंसान की एक आंख ज्यादा, जबकि दूसरी आंख कम प्रभावशाली होती है। प्रभावशाली आंख में कोशिकाओं की बनावट गोलाकार होती है, जबकि दूसरी आंख की बनावट अंडाकार होती है। यही कारण है कि प्रभावशाली आंखें हमेशा सटीक तस्वीर मुहैया कराती हैं।

डिसलेक्सिया दिमागी बीमारी नहीं

डिसलेक्सिया को दिमागी बीमारी के रूप में देखा जाता है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है। पर नए अध्ययन के मुताबिक, यह मस्तिष्क से नहीं, बल्कि आंखों की कोशिकाओं से जुड़ी बीमारी है। रॉयल सोसायटी के जर्नल में छपे अध्ययन के मुताबिक, बच्चों में इस बीमारी के लिये उनकी आंखों की पुतली यानी रेटिना के भीतर की कोशिकाओं का असामान्य आकार जिम्मेवार हो सकता है।

दोनों आंखों का एक समान होना खतरनाक

जिन लोगों में डिसलेक्सिया होता है उनकी दोनों आंखों की कोशिकाओं की बनावट एक जैसी होती है। ये गोलाकार भी हो सकती है और अंडाकार भी। ऐसे में दोनों आंखों में प्रभावशाली होने की होड़ सी लगी रहती है। इस होड़ के चलते मस्तिष्क असमंजस में पड़ जाता है कि वह किस आंख की बनाई प्रतिबिंब ले और उसे आगे पहुंचाएं। शोधकर्ताओं के अनुसार, दोनों आंखों की इसी लड़ाई के चलते मस्तिष्क अक्षरों की सही जानकारी भी हासिल नहीं कर पाता, जिसके कारण अक्षर उलटे–पुलटे दिखाई पड़ते हैं।

स्वास्थ्य संबंधी जानकारी

- RO का पानी कभी ना पियें यह गुणवत्ता को स्थिर नहीं रखता। कुएँ का पानी पियें। बारिस का पानी सबसे अच्छा, पानी की सफाई के लिए सहिजन की फली सबसे बेहतर है।
- सोकर उठते समय हमेशा दायीं करवट से उठें या जिधर का स्वर चल रहा हो उधर करवट लेकर उठें।
- पेट के बल सोने से हर्निया, प्रोस्टेट, एपेंडिक्स की समस्या आती है।
- भोजन के लिए पूर्व दिशा, पढ़ाई के लिए उत्तर दिशा बेहतर है।
- HDL बढ़ने से मोटापा कम होगा LDL व VLDL कम होगा।
- गैस की समस्या होने पर भोजन में अजवाइन मिलाना शुरू कर दें।
- चीनी के अन्दर सल्फर होता जो कि पटाखों में प्रयोग होता है, यह शरीर में जाने के बाद बाहर नहीं निकलता है। चीनी खाने से पित्त बढ़ता है।
- शुक्रोज हजम नहीं होता है फ्रेक्टोज हजम होता है और भगवान की हर मीठी चीज में फ्रेक्टोज है ।
- वात के असर में नींद कम आती है।
- कफ के प्रभाव में व्यक्ति प्रेम अधिक करता है।
- कफ के असर में पढ़ाई कम होती है।
- पित्त के असर में पढ़ाई अधिक होती है।
- आँखों के रोग-कैट्रेक्टस, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, आँखों का लाल होना आदि ज्यादातर रोग कफ के कारण होता है।
- शाम को वात-नाशक चीजें खानी चाहिए।
- प्रात: 4 बजे जाग जाना चाहिए ।
- सोते समय रक्त दबाव सामान्य या सामान्य से कम होता है ।
- व्यायाम - वात रोगियों के लिए मालिश के बाद व्यायाम, पित्त वालों को व्यायाम के बाद मालिश करनी चाहिए। कफ के लोगों को स्नान के बाद मालिश करनी चाहिए।
- भारत की जलवायु वात प्रकृति की है, दौड़ की बजाय सूर्य नमस्कार करना चाहिए।
- जो माताएं घरेलू कार्य करती हैं उनके लिए व्यायाम जरुरी नहीं।
- निद्रा से पित्त शांत होता है, मालिश से वायु शांति होती है, उल्टी से कफ शांत होता है तथा उपवास से बुखार शांत होता है।
- भारी वस्तुयें शरीर का रक्तदाब बढ़ाती है, क्योंकि उनका गुरुत्व अधिक होता है।
- दुनिया के महान वैज्ञानिक का स्कूली शिक्षा का सफर अच्छा नहीं रहा, चाहे वह 8 वीं फेल न्यूटन हों या 9वीं फेल आइस्टीन हों।
- माँस खाने वालों के शरीर से अम्ल-स्राव करने वाली ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं।
- तेल हमेशा गाढ़ा खाना चाहिए सिर्फ लकड़ी वाली घाणी का, दूध हमेशा पतला पीना चाहिए।
- छिलके वाली दाल-सब्जियों से कोलेस्ट्रोल हमेशा घटता है।
- कोलेस्ट्रोल की बढ़ी हुई स्थिति में इन्सुलिन खून में नहीं जा पाता है। ब्लड शुगर का सम्बन्ध ग्लूकोस के साथ नहीं अपितु कोलेस्ट्रोल के साथ है।
- मिर्गी दौरे में अमोनिया या चूने की गंध सूँघानी चाहिए।
- सिरदर्द में एक चुटकी नौसादर व अदरक का रस रोगी को सुंघायें।
- भोजन के पहले मीठा खाने से बाद में खट्टा खाने से शुगर नहीं होता है।
- भोजन के आधे घंटे पहले सलाद खाएं उसके बाद भोजन करें।
- अवसाद में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी हो जाती है। फास्फोरस गुड़ और अमरुद में अधिक है।
- पीले केले में आयरन कम और कैल्शियम अधिक होता है। हरे केले में कैल्शियम थोड़ा कम लेकिन फास्फोरस ज्यादा होता है तथा लाल केले में कैल्शियम कम आयरन ज्यादा होता है। हर हरी चीज में भरपूर फास्फोरस होती है, वही हरी चीज पकने के बाद पीली हो जाती है जिसमे कैल्शियम अधिक होता है।
- छोटे केले में बड़े केले से ज्यादा कैल्शियम होता है।
- रसौली की गलाने वाली सारी दवाएँ चूने से बनती हैं।
- हेपेटाइट्स A से E तक के लिए चूना बेहतर है।
- एंटी टिटनेस के लिए हाईपेरियम 200 की दो-दो बूंद 10-10 मिनट पर तीन बार दें।
- ऐसी चोट जिसमे खून जम गया हो उसके लिए नैट्रमसल्फ दो-दो बूंद 10-10 मिनट पर तीन बार दें। बच्चों को एक बूंद पानी में डालकर दें ।
- मोटापे में कैल्शियम की कमी होती है अत: त्रिफला दें। त्रिकूट (सोंठ+कालीमिर्च+मघा पीपली) भी दे सकते हैं।

कण–कण में व्याप्त हैं भगवान

भगवान कण–कण में विराजमान हैं। यह बौद्धिकता है, किंतु परमात्मा को प्रकट करना हार्दिकता है। तन के लिए जीतना भोजन आवश्यक है, मन के लिए भजन उतना ही आवश्यक है, जैसे बिना भूख के समय होने पर भोजन कर लेते हैं, वैसे ही मन न लगने पर समय से भजन करें। परमात्मा का मिलन संत की कृपा से होता है। राम–सुग्रीव का मिलन भगवान हनुमान जी जैसे संत ही करा सकते हैं। जब कोई काल से डरता है तो संत भगवान की स्मृति दिलाकर उसे निर्भय करते हैं। जब कोई भगवान से न डरे तो संत काल का भय दिखाकर उसमें भय उत्पन्न कर भगवान से जोड़ देते हैं। विभीषण ने हनुमान जी में भगवान को देखा। भक्ति विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं। जैसे पानी में बिजली है, इसको जानकार बिजली पैदा करते हैं, यह विज्ञान है। कण–कण में परमात्मा विराजमान हैं। यह भाव ही श्रेष्ठ है। जिस प्रकार से सूर्योदय होने से घोर कोहरा छंट जाता है, उसी प्रकार भक्ति से पाप कर्म धुल जाता है। कितनी ही धर्मार्थ यात्रा, गंगा स्नान, यज्ञ, धर्म, पाठ कर लें, किंतु एक भक्ति ही उसे अपने अधीन बना लेती है। सच्चे भक्त को कर्म–धर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान जिनके रोम–रोम में है, जिसके मुंह से सूर्य के समान ज्वालाएं निकल रही हैं, जिनमें अनंत मात्रा का ऐश्वर्य हो, ऐसे श्रीकृष्ण ही हैं। उनकी हमें पांच भावों – शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की उपासना करनी चाहिए। इन सबमें श्रेष्ठ माधुर्य भाव ही है।

माधुर्य भाव ही सर्वाधिक सामिप्य है। इस भाव में हम प्रेयसी हैं, वे हमारे प्रियतम हैं, ऐसी भावना निरंतर रहती है। अब लौकिक उदाहरण के अनुसार जैसे प्रेयसी का संबंध पति से अत्यंत निकट का होता है, पुत्र का उससे कम, सखा का उससे कम, दास का उससे भी कम तथा प्रजा का संबंध कम निकट का होता है। हमें भगवान श्रीकृष्ण की माधुर्य भाव से भक्ति करनी चाहिए।

पाक्षिक पंचांग

13 से 26 अक्टूबर 2025
विक्रम संवत् 2082
कार्तिक कृष्ण 7 से कार्तिक शुक्ल 5 तक

दि.	माह	वार		तिथि/त्यौहार
13	अक्टूबर	सोम	कार्तिक कृष्ण	7
14	अक्टूबर	मंगल	----------	8
15	अक्टूबर	बुध	----------	9
16	अक्टूबर	गुरु	----------	10
17	अक्टूबर	शुक्र	----------	11 रंभा एकादशी
18	अक्टूबर	शनि	----------	12 प्रदोष व्रत, धनतेरस
19	अक्टूबर	रवि	----------	13 शिव चतुर्थी व्रत
20	अक्टूबर	सोम	----------	14 दीपावली
21	अक्टूबर	मंगल	----------	30 स्ना.दा. अमावस्या
22	अक्टूबर	बुध	कार्तिक शुक्ल	1 गोवर्धन पूजा
23	अक्टूबर	गुरु	----------	2 भाई दोज
24	अक्टूबर	शुक्र	----------	3
25	अक्टूबर	शनि	----------	4 विनायकी चतुर्थी व्रत
26	अक्टूबर	रवि	----------	5 पांडव पंचमी

नर्मदा नहर परियोजना की जल वितरण समिति की बैठक

टेल लाइन पर किसानों को मिले पर्याप्त पानी : श्री विश्नोई

जयपुर। नर्मदा नहर परियोजना में रबी फसल वर्ष 2025 -26 की अवधि में जल प्रवाहित करने के लिए जल वितरण समिति की बैठक राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री व जालोर जिले के प्रभारी मंत्री श्री के.के.विश्नोई व बाड़मेर सांसद श्री उम्मेदाराम बेनीवाल की उपस्थिति तथा संभागीय आयुक्त जोधपुर डॉ. प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में जालोर जिले में नर्मदा नहर परियोजना के विश्राम गृह सांचौर में आयोजित की गई।

बैठक में राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री के.के. विश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आमजन के उत्थान एवं विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि नर्मदा नहरी तंत्र को विकसित, आधुनिक एवं सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा बजट का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि नर्मदा नहर परियोजना के माध्यम से हेड क्षेत्र जे साथ ही टेल कमांड क्षेत्र में आने वाले किसानों को भी कृषि एवं सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा पानी पहुंचाया जाए।

बाड़मेर सांसद श्री उम्मेदाराम बेनीवाल जल वितरण की वर्तमान स्थिति एवं सामने आ रही चुनौतियों, जल के समुचित वितरण व किसानों को समय पर जल उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने की बात कही।

बैठक में नर्मदा बेसिन के सरदार सरोवर बाँध में वर्ष 2025-26 के लिए पानी की उपलब्धता, रबी फसल में परियोजना में स्वीकृत सिंचाई तीव्रता, उपलब्ध पानी से आगामी रबी सिंचाई के लिए माह नवम्बर 2025 से मार्च 2026 तक नहरों में प्रवाहित किये जाने वाले जल की मात्रा एवं रेगुलेशन कार्यक्रम के निर्धारण,. अवैध पानी चोरी रोकथाम, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, वाली छोटी नहरों, माइनर्स, सब माइनरो सील्ट व गाद हटाने को लेकर चर्चा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

बैठक में चौहटन विधायक श्री आदूराम मेघवाल, जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे, जिला पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह इंदोलिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर सांचौर दौलतराम चौधरी सहित विभागीय अधिकारी-कार्मिक एवं कृषक उपस्थित रहे।

छोटा विज्ञापन बड़ा लाभ

व्यक्तिगत क्लासीफाइड

विज्ञापन के लिए निर्धारित कैटेगरीज-

- बेचना/खरीदना- ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेशर, खेत, मकान, मोटरसाइकल, पशु, मोटर, जनरेटर आदि
- बीज ▪ औषधीय फसल

विज्ञापन दर - मात्र रु. 600/- प्रति संस्करण लगातार 4 सप्ताह तक

- अधिकतम 25 शब्द
- अतिरिक्त शब्द- 2 रु. प्रति शब्द, अधिकतम 40 शब्दों तक

डिस्प्ले क्लासीफाइड

विज्ञापन दर : रु. 800/- प्रति अंक, प्रति संस्करण
साइज : फिक्स साइज- 8 × 5 = 40 वर्ग से.मी.

कैटेगरीज- बीज, कीटनाशक, जैविक खाद, ट्रेवल्स, तीर्थ यात्रायें, आवश्यकता, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कृषि सेवा केन्द्र, शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण, बारदाने, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, होस्टल,

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ

केवीके पोकरण में हुआ लाइव टेलीकास्ट

पोकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 42 हजार करोड़ रुपये की कृषि परियोजनाओं सहित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), पोकरण में कार्यक्रम का सजीव प्रसारण आयोजित किया गया, जिसमें गोमट, रामदेवरा, एका, थाट, बिलिया और केलावा सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में किसान और महिला कृषक शामिल हुए।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महन्त प्रतापपुरी, विधायक पोकरण ने कहा कि प्रधानमंत्री की ये योजनाएँ सीमांत जिलों के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी। उन्होंने किसानों से खेती और पशुपालन में नई तकनीक एवं नवाचार अपनाने, थारपारकर और गिर नस्ल की गायों के संवर्धन तथा दुग्ध उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचकर आय बढ़ाने का आह्वान किया।

केवीके के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉ. दशरथ प्रसाद ने बताया कि इन योजनाओं के तहत जैसलमेर जिले को विशेष रूप से चयनित किया गया है। इनसे किसानों को अनुदान, नवाचार और आधुनिक तकनीकों का लाभ मिलेगा। काजरी, जैसलमेर के अध्यक्ष डॉ. आर. एस. मेहता ने रबी फसलों जैसे जीरा और इसबगोल में कीट एवं रोग प्रबंधन पर प्रकाश डालते हुए जलवायु अनुकूल किस्मों और प्राकृतिक खेती को अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ) बनाकर अपनी फसलों का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में डॉ. के. जी. व्यास, डॉ. सुनील कुमार शर्मा, डॉ. राम निवास, डॉ. सुगन चांद मीणा, डॉ. शिरीन, डॉ. अनिल पाटीदार सहित काजरी और वैज्ञानिक तथा किसानों ने भाग लिया।

सहकार सदस्यता अभियान

राज्य की भण्डारण क्षमता में होगी वृद्धि, किसानों की उपज रहेगी सुरक्षित

जयपुर। राज्य में 'सहकार सदस्यता अभियान' के अंतर्गत अन्य गतिविधियों के साथ ही भूमिविहीन सहकारी समितियों के लिए गोदाम निर्माण हेतु भूमि का चिह्नीकरण कर आवंटन करवाने की कार्यवाही भी एक प्रमुख गतिविधि के रूप में की जा रही है। अभियान के अंतर्गत बड़ी संख्या में समितियों द्वारा भूमि चिह्नीकरण की कार्यवाही कर आवंटन के लिए आवेदन किया जा चुका है। भूमि आवंटन हो जाने से इन समितियों में गोदाम के निर्माण की राह प्रशस्त होगी, जिससे राज्य की भण्डारण क्षमता में आशातीत वृद्धि होगी।

राज्य में ऐसी 1,975 पैक्स एवं 42 केवीएसएस हैं, जो या तो भूमिविहीन हैं या फिर जिनके पास गोदाम निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि नहीं है। अभियान के अंतर्गत पूरे मनोयोग से प्रयास कर अधिक से अधिक समितियों हेतु गोदाम निर्माण के लिए भूमि चिह्नीकरण कर आवंटन करवाने की कार्यवाही की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 1,145 पैक्स एवं 22 केवीएसएस द्वारा भूमि चिह्नीकरण की कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी है। वहीं, 1,112 पैक्स एवं 26 केवीएसएस द्वारा भूमि का आवंटन करवाने के लिए आवेदन किया गया है। इन समितियों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया भी तेज गति से सम्पन्न करवाई जा रही है।

78 वर्ष

कृषक जगत
राष्ट्रीय कृषि अखबार
भोपाल-जयपुर-रायपुर

वर्ष में कई आकर्षक एवं संग्रहणीय विशेषांक

- खरीफ विशेषांक
- पौध संरक्षण विशेषांक
- रबी विशेषांक
- बीज विशेषांक
- बागवानी विशेषांक

25 लाख पाठक

कृषक जगत की सदस्यता राशि
⇨ वार्षिक रु. 600/- ⇨ दो वर्ष रु. 1000/-
⇨ तीन वर्ष रु. 1500/-

डाक से नियमित रूप से **'कृषक जगत'** – प्रति सप्ताह ☐ भोपाल ☐ जयपुर ☐ रायपुर संस्करण निम्न पते पर एक वर्ष/दो वर्ष / तीन वर्ष भेजें. (अपनी आवश्यकता के अनुरूप निशान लगायें).

नाम .....
.....
ग्राम .....पो. .....
डाक वितरण हेतु अपने क्षेत्रीय पोस्टमैन का मो. नं. अवश्य दें : .....
वि.ख. ..... तह. .....
जिला ..... पिन ☐☐☐☐☐☐ राज्य .....
शिक्षा ..... भूमि ..... उम्र .....
ट्रैक्टर/मॉडल ..... फोन/मो. .....
ई-मेल .....
मेरा सदस्यता शुल्क रुपये ..... नगद/डिमांड ड्राफ्ट/UPI/Bank/
मनीऑर्डर/क्र. ..... 'कृषक जगत' भोपाल के नाम संलग्न है।

कृषक जगत में सदस्यता लेने के माध्यम
कृषक जगत ऑनलाइन पेमेंट लिंक
http://www.krishakjagat.org/krishak-jagat-subscription/index.php

Online Payment- SBI-A/C No. 53007193070, IFSC : SBIN 0005793,
Google Pay/Phone Pe/PAYTM/UPI : Mobile 9826255861
कृषक जगत हेल्पलाइन नम्बर 6262166222

पेमेंट के बाद : 1. पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें इस फोन नम्बर पर 9826255861
2. पूरा नाम, पता पिन कोड के साथ भेजें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें
प्रसार प्रबंधक कृषक जगत

भोपाल : 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल-462011 फोन: 0755-4248100, मो. : 9926653355, 9826255861, E-mail-info@krishakjagat.org
जयपुर : एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राज.), मो. : 9829254092, 7387422952
रायपुर : एलआईजी-5, सेक्टर-2, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.),मो.: 9826255862
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास इंदौर, मो. : 9826021837, 9826024864
नई दिल्ली : 403,आईएनएस बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली, मो. : 7387422952

सदस्यता शुल्क भुगतान के लिए QR कोड स्कैन करें

'समुन्नति एफपीओ कॉन्क्लेव 2025'

साझेदारी से मजबूत होते किसान उत्पादक संगठन

नई दिल्ली (कृषक जगत)। कृषि क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 5वां समुन्नति एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 सितंबर माह में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम समुन्नति और नाबार्ड के संयुक्त तत्वावधान में हुआ।

इस कॉन्क्लेव में देशभर के किसान संगठनों, कृषि-उद्योगों और नवाचारकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य साझेदारी के ज़रिए भविष्य के लिए तैयार एफपीओ पारितंत्र को मज़बूत बनाना था। हैदराबाद में 3-4 सितम्बर को हुए दो दिवसीय कॉन्क्लेव का विषय था - 'सस्टेनेबिलिटी के लिए साझेदारी: भविष्य के लिए तैयार एफपीओ पारितंत्र की ओर।'

इसमें देशभर से 2,500 से अधिक प्रतिनिधि, 1,000 एफपीओ नेता, 300 पारिस्थितिकी भागीदार और 100 स्टार्टअप्स व कृषि उद्यम शामिल हुए।

एफपीओ आंदोलन को मिली नई दिशा

एफपीओ कॉन्क्लेव का मकसद सिर्फ चर्चा करना नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करना था। इस साल का सम्मेलन दिखाता है कि अब एफपीओ नीतिगत मंचों से आगे बढ़कर ग्रामीण विकास के मज़बूत व्यावसायिक केंद्र बन रहे हैं।

कार्यक्रम में 'स्टेट ऑफ द सेक्टर रिपोर्ट - एफपीओ 2025' जारी की गई, जिसे नेशनल एसोसिएशन फॉर एफपीओ (NAFPO) ने तैयार किया है।

इस रिपोर्ट में भारत के 44,000 से अधिक एफपीओ का विश्लेषण किया गया है और 'Ease of Doing Business for FPOs Index' के ज़रिए बताया गया है कि कौन से राज्य एफपीओ के विकास के लिए सबसे बेहतर माहौल प्रदान कर रहे हैं।

इसके पूर्व उद्घाटन सत्र में समुन्नति के संस्थापक और सीईओ श्री अनिल कुमार एस.जी. ने कहा कि भारत की कृषि में बड़ी संभावनाएँ हैं, जिन्हें साझेदारी और नवाचार के ज़रिए ही साकार किया जा सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि सरकार एफपीओ को ग्रामीण समृद्धि का प्रमुख इंजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। समुन्नति फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री प्रवेश शर्मा ने कहा कि एफपीओ पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से मजबूत हो रहा है, जो रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से जमीनी स्तर पर बदलाव ला रहा है। उन्होंने प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे ऐसा भविष्य बनाएं, जहाँ सामूहिक उद्यम, नवाचार और बेहतर बाजार संपर्क देश के लाखों छोटे किसानों के जीवन में सुधार लाएं। नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद ने कहा कि कृषि का भविष्य जलवायु-संवेदनशील, सामूहिक और बाज़ार-केंद्रित ढांचे में है।

ग्राम हाट से लेकर ग्लोबल मार्केट तक

आईटीसी लि. में कृषि एवं आईटी समूह प्रमुख श्री शिवकुमार ने एक विशेष फायरसाइड सत्र में कहा कि कृषि-विपणन पारंपरिक हाट से आगे बढ़कर अब डिजिटल आपूर्ति श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने बताया कि आईटीसी प्रौद्योगिकी आधारित स्थायी मूल्य श्रृंखलाओं और एफपीओ के साथ सहयोगात्मक बाजार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शिवकुमार ने समावेशी विकास और किसान सशक्तिकरण को कंपनी की प्रमुख रणनीति बताया। वहीं सह्याद्री फार्म्स के श्री विलास शिंदे, कोर्टेवा एग्रीसाइंस के श्री सुब्रतो गीड और ओलम ग्रुप के श्री एन. मुत्थुकुमार ने मूल्य श्रृंखला के एकीकरण, विज्ञान-आधारित नवाचार और जलवायु-स्मार्ट कृषि पर अपने विचार साझा किए। समापन सत्र में समुन्नति के चेयरमैन श्री एन. श्रीनिवासन ने कहा, 'एफपीओ कॉन्क्लेव केवल एक वार्षिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि किसानों को केंद्र में रखकर बाजार, वित्त और नवाचार को जोड़ने की हमारी प्रतिबद्धता है।'

इसके साथ ही, समुन्नति और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (BMGF) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट 'बिल्डिंग एन एनेबलिंग इकोसिस्टम फॉर इंडियन FPOs' भी जारी की गई।

इसमें बताया गया है कि वित्त, बाज़ार, तकनीक और सलाहकारी सेवाओं की बेहतर पहुँच से एफपीओ को मजबूत और निवेश योग्य संस्थाओं में बदला जा सकता है।

एफपीओ स्केलएक्स प्रोग्राम की शुरुआत

कॉन्क्लेव की सबसे बड़ी घोषणा रही 'एफपीओ स्केलएक्स' कार्यक्रम की शुरुआत। इसका लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में 300 एफपीओ को रू. 100 करोड़ क्लब में पहुँचाया जाए, जिन्हें 'यूनिकॉर्न एफपीओ' कहा गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन एफपीओ को टिकाऊ, मज़बूत और बाज़ार में अग्रणी संस्थाओं के रूप में विकसित करना है।

इसी दौरान पीएफआरडीए (PFRDA) के कार्यकारी निदेशक ने किसानों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से जोड़ने पर ज़ोर दिया और इसे किसानों के लिए 'दूसरी फसल' बताया, जो ग्रामीण परिवारों को लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा देगी।

नेताओं ने रखी कृषि के भविष्य की रूपरेखा डिजिटल कृषि की दिशा में बड़ा कदम - यूकेआई पहल

कॉन्क्लेव के दौरान आरती इंडस्ट्रीज़ के श्री मिरिक गोगरी और यूकेआई के श्री अनुराग दीक्षित ने समुन्नति के साथ यूनिफाइड कृषि इंटरफेस (UKI) की घोषणा की, जो किसानों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। यह प्लेटफ़ॉर्म किसानों को बीज, खाद, सलाह, तकनीकी सेवाओं और उपकरणों तक एक ही माध्यम से पहुँच देगा ।यह परियोजना फिलहाल नासिक में पायलट चरण में है ।

खेत से आई प्रेरक कहानियाँ

कॉन्क्लेव के विशेष सत्र 'इनसाइट्स फ्रॉम द फील्ड' में दो किसानों के नेतृत्व वाले संगठनों की कहानियाँ विशेष आकर्षण रहीं। नॉर्दर्न फार्मर मेगा एफपीओ के संस्थापक श्री पुनीत सिंह थिंद और मिष्टि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशक श्री संजीव ने बताया कि कैसे सामूहिक उद्यम से किसानों की आय, बाजार पहुँच और संस्थागत क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इन उदाहरणों ने यह दिखाया कि संगठित प्रयास और नवाचार मिलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायित्व और ताकत दे सकते हैं।

कृषि परिवर्तन का साझा मंच

कॉन्क्लेव के दौरान नाबार्ड पैवेलियन में देशभर के एफपीओ ने अपने उत्पाद और नवाचार प्रदर्शित किए। प्रदर्शनी में स्टार्टअप्स, कंपनियाँ और वित्तीय संस्थाएँ भी शामिल रहीं, जिसने इस आयोजन को एक जीवंत सहयोग मंच में बदल दिया। राष्ट्रीय कृषि अखबार कृषक जगत इस कॉन्क्लेव का मीडिया पार्टनर रहा। कॉन्क्लेव के समापन पर यह संदेश स्पष्ट था- एफपीओ का विकास ही भारत के कृषि परिवर्तन की धुरी है। समुन्नति एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 ने यह दिखाया कि जब साझेदारी, नवाचार और समावेशिता एक साथ आती हैं, तो भारत का ग्रामीण परिदृश्य न केवल आत्मनिर्भर बल्कि भविष्य के लिए तैयार बनता है।

डेनमार्क गए किसानों एवं पशुपालकों ने एग्रो फूड पार्क का किया विजिट

दोनों देशों द्वारा अपने अनुभवों और जानकारियों को साझा किया गया

जयपुर। किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत 38 प्रगतिशील किसानों का दल तीन मंत्रियों के नेतृत्व में इन दिनों डेनमार्क दौरे पर है। डेनमार्क में यह दल वहां कृषि और पशुपालन की नई तकनीकों और नवाचारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है। भ्रमण के दौरान इस दल की डेनमार्क के विभिन्न संगठनो के साथ बैठकें हो रही हैं जिसमें कृषि पशुपालन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों द्वारा अपने अनुभवों और जानकारियों को साझा किया जा रहा है। डेनमार्क गए किसानों एवं पशुपालकों ने अपने प्रवास के दूसरे दिन डेनमार्क के आहरस में एग्रो फूड पार्क का विजिट किया। वहां उन्होंने पशुओं के उन्नत आवास एवं दूध उत्पादन में वृद्धि, दूध की गुणवत्ता एवं शेल्फ लाइफ बढ़ाने आदि की नवीन तकनीक के विषय में विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त की।

बातचीत के दौरान पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने डेनमार्क की कंपनी के प्रतिनिधियों को राजस्थान में पशुपालन के क्षेत्र मे हो रहे निरंतर विकास और वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग के विषय में विस्तार से बताया। पशुपालन राज्य मंत्री श्री बेढम ने डेनमार्क में उपलब्ध नवीन तकनीकी का उपयोग कर राज्य की देसी नस्लों में दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु एवं डेनमार्क की तकनीकी को राजस्थान के संदर्भ में विकसित करने हेतु कार्य किए जाने की आवश्यकता बताई।

दल ने एक ऑर्गेनिक डेयरी फार्म का भ्रमण किया जहां गायों को पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक तरीके से पाला जा रहा है तथा ऑर्गेनिक दूध का उत्पादन किया जा रहा है। यह दूध किसान को-ऑपरेटिव के माध्यम से बाजार में अच्छे दामों में बेचा जाता है। भारत के किसानों ने इस पद्धति में बेहद रुचि दिखाई और इस पद्धति को प्रदेश में अपनाने की इच्छा जाहिर की।

किसानों के दल ने दौरे के पहले दिन पशुओं में नस्ल संरक्षण एवं संवर्द्धन द्वारा दूध उत्पादन बढ़ाने तथा पशुओं से संबंधित सभी डाटा को संग्रहित करने की आवश्यकता की जानकारी भी प्राप्त की।

उल्लेखनीय है इस दल में पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत, पंचायती राज व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री ओटा राम देवासी, पशुपालन राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढम, किसान आयोग के अध्यक्ष श्री सी आर चौधरी, पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा, कृषि विभाग के शासन सचिव श्री राजन विशाल के साथ साथ कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन विभागों के 9 अधिकारी तथा 38 किसान और पशुपालक भी शामिल हैं। दल का नेतृत्व पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत कर रहे हैं।

यह दल अपना दौरा पूरा करेगा और कोपेनहेगन से रवाना होकर नई दिल्ली पहुंचेगा। इस अध्ययन दौरे में किसानों को कृषि और पशुपालन क्षेत्र में नवाचार, जैव उर्वरक प्रयोग, पशुपालन में तकनीकी सुधार और विपणन प्रणाली की गहन जानकारी मिलेगी। दौरे से लौटने के बाद ये किसान अपने अनुभवों को स्थानीय स्तर पर साझा करेंगे और इससे प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र को लाभ मिलेगा।

कृषि विभाग के सभी एमओयू को शत - प्रतिशत क्रियान्वित करने के लिए विभाग कृत संकल्पित : श्री विशाल

जयपुर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंतर्गत संपादित एमओयू के क्रियान्वयन को गति देने एवं निवेशकों को ग्राउंड ब्रेकिंग व प्रोत्साहित करने के लिए कृषि, उद्यान, कृषि विपणन विभाग और कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मंगलवार को शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री राजन विशाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान 253 करोड़ रुपये के निवेश की 5 नयी अन्न भण्डारण की आधुनिक साइलो निर्माण की परियोजनाओं का भी अनुमोदन किया गया।

बैठक में शासन सचिव ने बताया कि राइजिंग राजस्थान में आए एमओयू को पूरा करने के लिए कृषि विभाग गंभीर है और विभाग सभी एमओयू को शत प्रतिशत क्रियान्वित करने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भूमि धारक निवेशकों जिन्होंने राइजिंग राजस्थान में एमओयू कर रखा है उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग में आ रही समस्याओं की जानकारी लेकर उनका समाधान करना है।

श्री राजन विशाल ने बताया कि राज्य में उद्योग विभाग के बाद दूसरे नम्बर पर सबसे अधिक एमओयू लगभग 2 हजार 439 कृषि क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। जिनमें से विभाग द्वारा लगभग 26 प्रतिशत एमओयू को धरातल पर क्रियान्वित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान से प्राप्त एमओयू के क्रियान्वयन की मॉनिट्रिंग मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और शासन सचिव स्तर से लगातार की जा रही है।

उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान अभूतपूर्व समावेसी एवं सतत् आर्थिक व सामाजिक विकास तथा लोगों के कल्याण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण मिशन साबित हुआ है।

जिला कलेक्टर जयपुर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा जयपुर जिले में भू-राजस्व से संबंधित रूपान्तरण, नामान्तरण, रास्ते आदि के लंबित प्रकरणों का मौके पर ही प्रक्रियात्मक जानकारी देते हुए उच्च प्राथमिकता के साथ निस्तारण करवाए जाने का आश्वासन दिया गया। कृषि विपणन विभाग के निदेशक श्री राजेश कुमार चौहान द्वारा विपणन बोर्ड स्तर पर एमओयू मोनिटरिंग के लिए विशिष्ठ सेल के गठन एवं क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए निवेशकों को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला स्तर की मंडी के सचिव (नोडल अधिकारी) तथा एमओयू सेल के अधिकारीयों से संपर्क कर समयबद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने का आव्हान किया गया। आयोजन में निवेशकों के साथ सम्बंधित विभागीय अधिकारीयों द्वारा भी भाग लिया गया।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमती विनिता सिंह, महाप्रबंधक राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड श्रीमती संतोष करोल सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

सर्वोत्तम गुणवत्तावाली
जैन ड्रिप की विस्तृत उत्पादन श्रृंखला -
सभी फसलों # के लिए हर किसान के बजट के
अनुरूप विभिन्न प्रकार के ड्रिप सिचाई व्यवस्था
के विकल्प स्टॉक में उपलब्ध हैं।
(# दलहन, धान, तिलहन, सब्जियाँ एवं फल बागानें आदि के लिए)

जैन टर्बो स्लिम - टीई व सुपर सेव्हर
5 से 20 मील (0.13 से 0.5 मिमी)
साईज - 12, 16, 20 मिमी

जैन टर्बो एक्सेल प्लस
0.4 मिमी, क्लास 1 एचडी व क्लास 2
साईज - 12, 16, 20 मिमी

जैन टर्बो लाईन सुपर
0.4 मिमी, क्लास 1 एचडी व क्लास 2
साईज - 12, 16, 20 मिमी साईज

जैन टर्बो लाईन - पीसी
क्लास २
साईज - १६, २० मिमी

जैन टर्बो टॉप - एचडी पीसी
१३, १५ मील (0.33, 0.38 मिमी) - क्लास 1 व 2
साईज - 12, 16, 20 मिमी

जैन पॉलीट्यूब एवं ड्रिपर्स
साईज - 12, 16, 20, 25, 32 मिमी

नोट : ड्रिपर्स व ड्रिपलाईन अलग-अलग प्रेशर रेटींग में उपलब्ध

जैन® ड्रिप
प्रति बूँद, फसल भरपूर!®

जैन इरिगेशन सिस्टम्स् लि.
छोटे छोटे कदम, आसमान छूने का दम!®

दूरभाष: 0257-2258011; 6600800
टोल फ्री : 1800 599 5000
ई-मेल: jisl@jains.com; वेबसाईट: www.jains.com

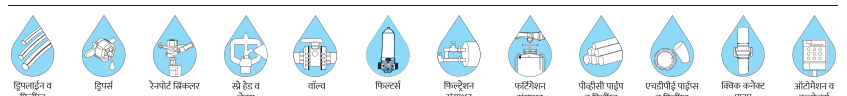

सावधान! नकल करके ड्रिप बनाने वाले एवं
नकली ड्रिप कंपनियों और वितरकों से सतर्क रहें!